

[2023] 8 एस. सी. आर 379

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

बी.

गोवा का राज्य

(2023 की सिविल अपील संख्या 3615)

10 मई, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और संजय कुमार, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 34 , 37- मध्यस्थ पुरस्कार-हस्तक्षेप का दायरा-आयोजित: मध्यस्थता पुरस्कार एक नहीं है साधारण न्यायनिर्णायक आदेश ताकि न्यायालयों द्वारा यू/एस. एस. द्वारा हल्के से हस्तक्षेप किया जाए। 34 या 37 मानो किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील या संशोधन से निपटना-एक पुरस्कार हो सकता है

कहा जाता है कि "पेटेंट अवैधता" से केवल तभी पीड़ित है जब यह पुरस्कार के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अवैध है और इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए।

साध्य के पुनः मूल्यांकन का तरीका-हस्तक्षेप की संभावना केवल तभी उत्पन्न होगी जब मध्यस्थ का निर्माण ऐसा हो जो किसी निष्पक्ष और उचित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता हो-"पेटेंट अवैधता" के संकीर्ण दायरे का उल्लंघन केवल विभिन्न अभिव्यक्तियों के उपयोग से नहीं किया जा सकता है जो फिर भी केवल "त्रुटि" का उल्लेख करते हैं और "पेटेंट अवैधता" के लिए नहीं-यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो पुरस्कार को निर्माण से प्राप्त कटौती के संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है-अदालतों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की वैधता की जांच करते समय संयम दिखाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा तथ्यात्मक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद पुरस्कार में हस्तक्षेप अधिनियम के उद्देश्य को पराजित करना होगा-तथ्यों पर, अपीलकर्ताओं ने निर्माण किया

मध्यस्थ, जिसमें अपीलकर्ताओं ने रुपये की राशि का अधिनिर्णय किया। 292.22

पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ, हालांकि, उच्च न्यायालय ने दी गई ब्याज दर को घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।

पुरस्कार के गुणों से संबंधित प्रमुख मुद्दे-पुरस्कार के सामने पेटेंट की अवैधता की कोई बात स्पष्ट नहीं है-चूंकि उस समय प्रचलित ब्याज दरें 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा में थीं, इसलिए मध्यस्थ ने पुरस्कार के बाद 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर देने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया और इसे घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं था। वहाँ कोई नहीं था

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में ऐसा दोष जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था

पैरामीटर और एसएस की परिधि के भीतर। 34/37 - इसका एक हिस्सा

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश, जो पुरस्कार और वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को संशोधित करता है, को दरकिनार कर दिया जाता है और पुरस्कार को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 मध्यस्थता आदेश एक सामान्य न्यायिक आदेश नहीं है ताकि अदालतों द्वारा इसमें हल्के से हस्तक्षेप किया जा सके।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 या 37 मानो किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण से संबंधित हो। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल एक अवैधता नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, बल्कि यह "66 एक पेटेंट अवैधता" होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पुरस्कार के सामने स्पष्ट होना चाहिए, न कि जिसे हटा दिया गया है। अभिवचनों और साक्ष्य के एक लंबे विश्लेषण के माध्यम से। बेशक, जब समझौते के नियम और शर्तें

शासन करने वाले पक्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, मामला अलग होगा और इस तरह की कमी वाले निर्णय को अधिनियम की धारा 28 (3) द्वारा सीधे प्रभावित किया जाएगा, जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लेनदेन पर लागू व्यापार के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने का आदेश देता है। यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो निर्माण से प्राप्त कटौती के संदर्भ में पुरस्कार को अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी संभावना हस्तक्षेप तभी उत्पन्न होगा जब मध्यस्थ का निर्माण किया जाए।

ऐसा है जिसे कोई भी निष्पक्ष और विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकता है। [पैरा 18] [433-डी-जी]

1.2 तत्काल मामला अनुबंध की मुद्रा के दौरान अनुबंध की शर्तों के मौलिक परिवर्तन का मामला नहीं था।

और उस मामले के लिए, पक्षों ने निश्चित रूप से संचार का आदान-प्रदान किया और एक समझौते को अस्तित्व में लाया, जिसे भले ही मूल के पूरक के रूप में माना जाए, लेकिन विशेष ईंधन के उपयोग के संबंध में भौतिक अंतर था।

और फिर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर) की विनिमय दर के संदर्भ में उस आधार पर चालान बढ़ाना। [पैरा 19.3] [436-बी-सी] रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

बी. गोवा का राज्य

1.3 इस मामले की जांच एक और कोण से की जा सकती है। यदि विनियम के साथ पक्षों द्वारा सहमत शर्तें

20.03.2013 से शुरू होने वाले संचारों को नजरअंदाज किया जाना था, जिसका परिणाम उन पक्षों के अनुबंध की ऐसी शर्तों की अनदेखी करना होगा जो अस्तित्व में आई थीं और जो दोनों के लिए बाध्यकारी थीं। इस प्रकार, इस तथ्य के साथ कि केवल सीमित विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया था (यानी कि क्या बिजली की आपूर्ति ईंधन की निश्चित दर और मुद्रा की निश्चित दर के आधार पर या परिवर्तनीय शुल्कों के आधार पर की जानी थी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण को गुमराह होने और इस तरह के विश्लेषण में प्रवेश करने के बजाय उठाए गए मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना उचित था जो इस मुद्दे के लिए उपयुक्त नहीं था। [पैरा 20] [436-सी-ई]

1.4 परिवर्तनीय से संबंधित पुरस्कार के संबंध में अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत चुनौती के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था। शुल्क लेते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय खंड 12.1 पर तथाकथित विचार न करने के आधार पर परिवर्तनीय आरोपों से संबंधित अधिनिर्णय को रद्द करने में सही नहीं रहा है। 4 12. 1 तक। 7 बिजली खरीद समझौता। [पैरा 21] [436-एफ]

1.5 उच्च न्यायालय ने, अधिकारिता की सीमा की याद दिलाते हुए भी, खंड 12.1 मानते हुए साक्ष्य को व्यापक रूप से विच्छेदित करके वही त्रुटि की। 4 12. 1 तक। 7 वे उन सामग्री प्रस्तावों पर बारीकी से विचार किए बिना मामले के निर्णायक थे जो विवाद का गठन करते थे और जिन्हें पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। के रूप में

परिवर्तनीय शुल्कों के संबंध में, न्यायाधिकरण के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या दावेदार उपयोग करते समय विदेशी मुद्रा की निश्चित दर के साथ निश्चित शुल्क पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था।

वैकल्पिक ईंधन। इस प्रश्न का निर्धारण अनिवार्य रूप से नए अनुबंध के संदर्भ में किया जाना था जो पक्षों के बीच संचार के आदान-प्रदान के साथ अस्तित्व में आया था। मध्यस्थ ने उस साक्ष्य के संदर्भ में और उसके विश्लेषण के बाद मामले का सटीक निर्णय लिया। यह न तो मध्यस्थ का मामला था कि उसने इस मुद्दे पर लागू अनुबंध की शर्तों को ध्यान में नहीं रखा था और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष था जिसे कोई भी निष्पक्ष या तर्कसंगत व्यक्ति संभवतः कभी प्रस्तुत नहीं कर सकता था। पक्षों द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रस्तुत मुख्य विवाद के आलोक में देखे जाने पर, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने [2023] 8 एस. सी. आर. की जांच नहीं की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रश्न कि क्या विचाराधीन पत्राचार के परिणामस्वरूप अनुबंध के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ है, हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाते हैं क्योंकि ईंधन के संबंध में अनुबंध की शर्तों का नवीनीकरण बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं था। मूल सवाल यह था कि नई शर्तें कैसे काम करेंगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कानून के अनुसार ठीक उसी के साथ व्यवहार किया। [पैरा 21.1] [436-एफ-एच; 437-ए-सी] 1.6 परिवर्तनीय प्रभावों से संबंधित अधिनिर्णय की मद में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अस्वीकृति में जो देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, वह कमोवेश अन्य मदों पर भी लागू होता है, जहां उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और अधिनिर्णय को पलट दिया है। इस तरह के हर मामले में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष में प्रवेश किया है

मामला जैसे कि एक नियमित अपील से निपट रहा हो। यह उच्च न्यायालय का धारा 34 और अधिनियम की धारा 37 की परिधि से परे यात्रा करने का एक स्पष्ट मामला रहा है। [पैरा 22] [437-डी-ई]

1.7 मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि क्षमता को कम करने से संबंधित मुद्दे को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था और पक्षों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जबकि उच्च न्यायालय ने दिनांकित प्रमाण पत्र के अर्थ और प्रभाव के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की चर्चाओं में कमियों को पाया और यह कि क्या दावेदार उस आधार पर कोई दावा कर सकता था या नहीं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी आगे बढ़ा

बैठक के कार्यवृत्त का विश्लेषण करें। यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एक विशेष साक्ष्य के साथ मूल्य और मूल्य का मामला है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संतोषजनक नहीं माना गया था; और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा सरकार के तर्क को अस्वीकार करना गलत पाया गया था। हालाँकि, इसके बाद, उच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि यह साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का मामला नहीं था, बल्कि कोई सबूत नहीं होने के कारण, पेटेंट अवैध था। [पैरा 23.3,24] [441-डी-एफ]

1.8 उच्च न्यायालय ने धारा 37 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की और इसकी सीमा के भीतर रहने के बजाय

अधिनियम की धारा 34 के तहत विचार, उस क्षेत्र में प्रवेश किया गया जो विशेष रूप से मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है। इस मद के संबंध में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया था, वह विशेष रूप से अभिलेख पर साक्ष्य और संबंधित रिलेएंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर उसका दृष्टिकोण था।

बी. गोवा का राज्य

तथ्य/कारक। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत या पेटेंट अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है ताकि इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। भले ही दो विचार संभव हों, न्यायालय अपने स्वयं के विचार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विचार से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। [पैरा 24.1] [442-एफ-जी]

1.9 अवमूल्यन से संबंधित मुद्दे के संबंध में प्रश्न, कि ओ. ई. एम. सिफारिशें प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दावेदार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, केवल साक्ष्य की सराहना के सिद्धांतों से संबंधित हैं। में।

नियमित न्यायनिर्णायक प्रक्रिया, न्यायालय मान सकता है साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत कुछ तथ्यों का अस्तित्व; और उसके चित्रण (छ) के संदर्भ में, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार है कि साक्ष्य जो हो सकता है लेकिन नहीं

यदि उत्पादित किया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगा जो इसे रोकता है। तथापि, किसी दिए गए मामले में, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निर्धारण करते समय, क्या मध्यस्थ ऐसा निष्कर्ष निकालता है

34 , यह एक पुरस्कार में सीमित हस्तक्षेप की सीमा को खोलेगा और कार्यवाही को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को बहन करेगा। धारा 34 के अधीन और धारा 37 के अधीन

पुरस्कार के खिलाफ नियमित अपील/संशोधन और इस तरह, उन सिद्धांतों का फिर से उल्लंघन करना कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में साक्ष्य की पुनः प्रशंसा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह प्रति बल दोहराया जाता है कि एक पुरस्कार को कहा जा सकता है

"पेटेंट अवैधता" से केवल तभी पीड़ित है जब यह पुरस्कार के सामने स्पष्ट रूप से एक अवैधता है और साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के माध्यम से इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए। प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में प्रस्तुतियाँ स्वयं के लोकाचार के प्रतिकूल हैं

1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 की आवश्यकता है और

अस्वीकार कर दिया। [पैरा 25] [442-एच; 443-ए-ई] 1.10 जहां तक अवमूल्यन के प्रश्न का संबंध है, दिनांकित प्रमाण पत्र के मूल्य से संबंधित प्रश्न और दावेदार द्वारा इस मुद्दे को पहले नहीं उठाने का प्रभाव फिर से सीधे साक्ष्य की सराहना के क्षेत्र में आएगा और निष्कर्ष को [2023] 8 एस. सी. आर. की प्रधानता पर प्रस्तुत करने की सीमा तक पहुंच जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से निर्णय में त्रुटि के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज करना चुनौती के तहत। किसी भी मामले में, यदि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, तो परिणाम केवल प्रत्येक पुरस्कार को न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील बनाने का होगा।

उन आधारों पर जो अन्यथा अपील या संशोधन के हैं और जिन्हें विधानमंडल द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत लेने की अनुमति नहीं है। [पैरा 25.1] [443-ई-एच]

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित। यह देखा गया है कि दोनों पक्षों ने 15.8 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिलिंग की एक विशेष पद्धति पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन साथ ही, भविष्य में किसी भी समय 19.8 मेगावाट आपूर्ति पर वापस जाने का अधिकार उनके पास बरकरार रखा। पक्षकारों के लेन-देन के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मामले पर एक विशेष दृष्टिकोण रखा। यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से था अस्वीकार्य या अविश्वसनीय। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। [पैरा 29] [445-बी]

1.13 नेट आउट का पहलू पक्षों के अनुबंध की शर्तों और उनसे प्राप्त की जाने वाली कटौती पर निर्भर करता है।

अभिलेख पर साक्ष्य। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 13.09.2014 और 18.09.2014 दिनांकित टिप्पणियों के आधार पर विशेष निष्कर्ष निकाला था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आपूर्ति से संबंधित अनुबंध के प्रावधानों पर विचार किया।

वी. गोवा का राज्य

गोवा सरकार द्वारा दावेदार को समर्थन शक्ति जब

मई 2014 से अगस्त 2014 की अवधि के लिए बिजली स्टेशन बंद था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने आगे संचार का उल्लेख किया जिसमें गोवा सरकार का निर्णय भी शामिल है कि बंद के दौरान किस दर पर शक्ति है।

अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया और पुरस्कार को अलग रखने के लिए उसके सामने दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः व्याख्या की। अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय के लिए इस तरह के दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी अनुमति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। [पैरा 30,31.1] [445-सी-एफ; 446-ई] 1.14 ब्याज के सवाल के संबंध में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पालन करना उचित था

संविदात्मक प्रावधान और अधिनियम की धारा 31 (7) के प्रावधान; और पूर्व-संदर्भ अवधि और उस अवधि के लिए ब्याज के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया है जिसके दौरान कार्यवाही मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी। राज्य यह तर्क देना सही नहीं है कि ब्याज मध्यस्थ को निर्देश की अवधि के दौरान नहीं दिया जा सकता था। इस पहलू के संबंध में, इस प्रभाव के लिए प्रस्तुतियाँ कि पूर्व-संदर्भ अवधि का ब्याज किसी भी बाध्यकारी कारणों पर आधारित नहीं था और ब्याज के लिए संविदात्मक प्रावधान क्षेत्र में थे, खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, केवल 1996 के अधिनियम की धारा 34 की परिधि के भीतर भी नहीं होने के कारण खारिज किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक अधिनिर्णय के बाद की अवधि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए ब्याज की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज दर में उक्त कमी भी अनुचित है। धारा के प्रावधान

31 (7) (ख) जब तक पुरस्कार अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक मध्यस्थ पुरस्कार के तहत देय राशि पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से अधिक।

3] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में "ब्याज की वर्तमान दर" अभिव्यक्ति का वही अर्थ समझाया गया है जो

ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2 (बी) के तहत सौंपा गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय द्वारा प्रदत्त ब्याज को कम किया जा सकता है

मध्यस्थ जब ऐसा ब्याज प्रचलित आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है या जहां यह उचित नहीं पाया जाता है या जहां यह न्याय के हित को बढ़ावा देता है। ब्याज की दर को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का कोई आधार नहीं है। [पैरा 32.1,33,34] [446-जी-एच; 447-ए-बी, एफ-एच; 448-ए]

1.15 ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया है। इसके विपरीत, भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर होने के कारण प्रचलित ब्याज दर 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष के दायरे में थी। इस प्रकार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण

पुरस्कार के बाद 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 31 के तहत 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था और इसे घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय किसी भी इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था ताकि

ब्याज की दर को उसके द्वारा उचित समझे जाने पर पुनर्निर्धारित करना। यह एक वाणिज्यिक विवाद में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित मामला था। [पैरा 34.1] [448-सी-ई]

1.16 यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार के गुण-दोष से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है।

हालांकि, यह देखा गया है कि ऐसा नहीं था कि वाणिज्यिक न्यायालय ने इसके लिए उत्पन्न होने वाले भौतिक मुद्दों की जांच नहीं की थी

1996 के अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में मामले से निपटने के दौरान निर्धारण। [पैरा 35] [448-जी]

वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए बिंदुओं को तैयार करने और फिर यह देखने के बारे में टिप्पणी करें कि वाणिज्यिक न्यायालय ने केवल पुरस्कार के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत किया है। वाणिज्यिक न्यायालय धारा 34 आवेदन पर विचार करना अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। फिर भी, वाणिज्यिक न्यायालय ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों की गणना की।

बी. गोवा का राज्य

और फिर अभिलेख की जांच करने के बाद निष्कर्षों को वापस कर दिया और राज्य की ओर से की गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी, जिसमें 1996 के अधिनियम की धाराओं की परिधि के भीतर और मापदंडों पर उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया था। [पैरा 35.1] [448-एच; 449-ए-सी]

1.18 "पेटेंट अवैधता" के संकीर्ण दायरे का उल्लंघन केवल विभिन्न अभिव्यक्तियों के उपयोग से नहीं किया जा सकता है जो फिर भी केवल "त्रुटि" को संदर्भित करते हैं और "पेटेंट अवैधता" को नहीं। न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निर्णय की वैधता की जांच करते समय संयम दिखाने की आवश्यकता है, अन्यथा तथ्यात्मक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद निर्णय में हस्तक्षेप करना 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल करना होगा। यह इस तथ्य का एक हिस्सा है कि इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की कई न्यायिक घोषणाओं को निरर्थक बना देगा यदि मध्यस्थता पुरस्कारों को इन रूप में वर्गीकृत करके अलग रखा जाता है " इन अभिव्यक्तियों की आकृति की सराहना किए बिना विकृत या "स्पष्ट रूप से अवैध"। [पैरा 36] [450-बी-डी]

1.19 विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने हालांकि सांगयोग में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया

वे उपलब्ध थे और उन सिद्धांतों के संदर्भ में मामले से निपटने की आवश्यकता थी। इस पहलू को उस पर छोड़ते हुए, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह अवलोकन करना पर्याप्त होगा कि निर्णय और आदेश, जहां तक यह विचाराधीन पुरस्कार के निष्कर्षों और निष्कर्षों में हस्तक्षेप करता है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखने की आवश्यकता है। [पैरा 37] [450-डी-जी] [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.20 तथ्य यह है कि पेटेंट का कुछ भी नहीं है

पुरस्कार के चेहरे पर स्पष्ट अवैधता की ओर इशारा किया गया है। प्रस्तुतियाँ अनिवार्य रूप से मामले के गुण-दोष पर कुछ कथित त्रुटियों का संकेत देती हैं जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के मापदंडों के भीतर नहीं आती हैं। इसलिए, विवादित का वह हिस्सा

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जो वाणिज्यिक न्यायालय के पुरस्कार और आदेश को संशोधित करता है, को दरकिनार कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप, विचाराधीन पुरस्कार को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाता है। [पारस 38,39] [451-ए-सी]

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम

एनएचएआई: (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एससीआर 522;

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

(2015) 3 एससीसी 49: [2014] 13 एस. सी. आर. 895; दिल्ली हवाई अड्डा

मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड वी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम

लिमिटेड (2022) 1 एस. सी. सी. 131 पर निर्भर था।

वेदांता लिमिटेड v. शेनझेन शानदोंग परमाणु ऊर्जा

निर्माण कंपनी लिमिटेड: (2019) 11 एससीसी 465 [2018] 12

एससीआर 829-प्रतिष्ठित।

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163:

[2019] 3 एससीआर 1023; छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य। वी.

हकीम (2021) 9 एस. सी. सी. 1; पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स (पी)
लिमिटेड। वी . वी. ओ.

चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल

तूतीकोरिन और ओआरएस। (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 508 हरियाणा

टूरिज्म लिमिटेड v. कंधारी बेवरेजेस लिमिटेड (2022) 3 एससीसी

237 ; यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड बनाम हिमाचल राज्य
प्रदेश (2022) 4 एस. सी. सी. 116-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2022) 3 एस. सी. सी. 237

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.4

[2019] 3 एससीआर 1023

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.1

(2022) 2 एससीसी 275

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.2

(2021) 9 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.8

(2022) 4 एससीसी 116

संदर्भित किया गया है

पैरा 13.6

[2014] 13 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पैरा 18,37

[2018] 12 एससीआर 829

प्रतिष्ठित

पैरा 34 रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा का राज्य
(2022) 1 एससीसी 131

पैरा 36,37

उस पर भरोसा करें

[2019] 7 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3615

2023 तक।

उच्च न्यायालय के 08.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के सी. ओ. एम. ए. पी. संख्या 12 में गोवा में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 3616।

आर. वेंकटरमानी, एजी, रितिन राय, पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सुश्री रुचिरा गुप्ता, शिशिर देशपांडे, श्रीहर्ष पीचारा, सुश्री नैन्सी शाह, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, सुश्री नियति कोहली, सुश्री सुकृति भटनागर, अनिरुद्ध दुसाज, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री अंजलि सी., सुरेंद्र खोट, अग्नि सोम, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री की तालिका *

प्रारंभिक

2

प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमि

3
7

मध्यस्थता कार्यवाही और पुरस्कार।

.....

अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती।

..... 9

... .. 11

अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ।

... .. 15

प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान

..... 29

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने का दायरा तहत अपील का दायरा और अधिनियम की धारा 37 के

..... 33

.....

... .. 41

कार्यवाहियों और प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित पुरस्कार। 44

संयंत्र के अवमूल्यन से संबंधित पुरस्कार।

..... 58

4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित पुरस्कार

..... 65

नेट आउट सिद्धांत से संबंधित पुरस्कार

... 67

..... 68

पुरस्कार में रुचि।

अंतिम टिप्पणियां, अवलोकन और निष्कर्ष।

... 71

* एड। ध्यान दें: विषय-सूची में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभिक

छुट्टी दे दी गई।

2. बॉम्बे, गोवा बेंच में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की वाणिज्यिक अपील संख्या 12 में पारित किए गए 08.03.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ ये दो अपीलें, जिनमें से एक रिलायंस द्वारा की गई थी।

इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ', 2021 की एसएलपी (सिविल) No.8493 से उत्पन्न अपील होने के कारण; और दूसरा गोवा राज्य द्वारा, 2021 की एसएलपी (सिविल) No.16778 से उत्पन्न अपील होने के कारण, एक साथ विचार किया गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारे के लिए लिया गया है। 3. मध्यस्थता की धारा 37 के तहत एक अपील पर विचार करते हुए दिनांकित 08.03.2021 के विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से और

उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की धारा 13 के साथ पठित सुलह अधिनियम, 1996 3 उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, उत्तरी गोवा, पणजी द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा है। अधिनियम; और आंशिक रूप से 16.02.2018 दिनांकित पुरस्कार को अलग कर दिया है, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है जिसमें इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, एकमात्र मध्यस्थ शामिल हैं।

प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमि

4. अनावश्यक विवरणों से वंचित, प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं को उपयोगी रूप से संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है: 4.1 . 10.01.1997 पर, दावेदार ने गोवा सरकार के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।

14.08.1999 से 13.08.2014 की अवधि के लिए 39.8 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन केंद्र। बिजली स्टेशन को 'वैकल्पिक ईंधन' का उपयोग करने के प्रावधान के साथ बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में 'नाफ्था' का उपयोग करना था। दावेदार

14.08.1999 पर वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

4.2 . सितंबर 1997 से नवंबर 2001 तक दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पूरक समझौते किए गए। दिनांक 10.09.1997 के पहले पूरक बिजली खरीद समझौते द्वारा, उत्पादन केंद्र को ओपन साइकिल से बदलने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी

1 1 इसके बाद 'दावेदार' के रूप में भी संदर्भित किया गया। 2 इसके बाद इसे 'राज्य' या 'गोवा सरकार' भी कहा जाता है। 3 इसके बाद इसे '1996 का अधिनियम' या केवल 'अधिनियम' भी कहा जाता है। 4 इसके बाद इसे 'वाणिज्यिक न्यायालय' भी कहा जाता है।

5 ' पी. पी. ए. ', संक्षेप में।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

स्टेशन को एक संयुक्त साइकिल जनरेटिंग स्टेशन के रूप में उत्पन्न करना

क्षमता 48 मेगावाट। संविदित क्षमता को 39402 किलोवाट से बढ़ाकर 46560 किलोवाट कर दिया गया। इसके अलावा, दावेदार को संयुक्त चक्र के कारण उपभोक्ताओं को 39.8 मेगावाट से अधिक बिजली बेचने के लिए अधिकृत किया गया था

ऑपरेशन। 20.09.2000 पर, पक्षों के बीच दूसरा पूरक समझौता निष्पादित किया गया था, जिसने दावेदार को अनुमति के साथ उपभोक्ताओं को बिजली की कुछ प्रत्यक्ष बिक्री करने में सक्षम बनाया। द.

शुल्क की गणना 'नई निर्धारित क्षमता' पर आधारित थी, जिसे अनुबंधित क्षमता माना जाता था। इस समझौते में गोवा सरकार द्वारा दावेदार को समर्थन शक्ति का प्रावधान भी अनिवार्य किया गया था।

समझौते में निर्दिष्ट अनुसूचित या अनिर्धारित व्यवधानों के मामले में अपने उपभोक्ताओं को वितरण के लिए। 05.11.2001 पर, पक्षों ने तीसरा पूरक समझौता किया, जिसमें मार्च से दावेदार द्वारा 19.8 मेगावाट की सीमा तक बिजली की आपूर्ति में कमी को निर्दिष्ट किया गया था।

2004 पी. पी. ए. अवधि के अंत तक, यानी 13.08.2014 इस 19.8 मेगावाट क्वांटम को 'नई रेटेड क्षमता' के रूप में नामित किया गया था।

4.3 . ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली के महंगे होने को देखते हुए, गोवा सरकार ने दावेदार से खरीद को रोकने का इरादा किया और एक

20.03.2013 पर इस आशय का पत्र। हालाँकि, वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए पी. पी. ए. में एक प्रावधान को देखते हुए, दावेदार ने गोवा सरकार को रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस 6 का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति करने का अपना प्रस्ताव दिया, जिसे गेल द्वारा अपनी पाइपलाइन द्वारा गोवा लाया जा रहा था। दावेदार ने एक सूत्र दिया जिसके द्वारा बिजली की प्रति इकाई लागत का बिल गोवा सरकार को दिया जाएगा। वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने के दावेदार के प्रस्ताव और उस संबंध में देय शुल्क से संबंधित इस विशेष पहलू ने इस मामले में विवाद का एक बड़ा हिस्सा बनाया है। इसलिए, थोड़ा विस्तार उचित होगा।

4.3. 1 . 26.04.2013 पर, गोवा सरकार ने दावेदार के दिनांकित 21.03.2013 के पत्र का जवाब निम्नलिखित शब्दों में दिया: -

" आपके प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, सरकार

डब्ल्यू. ई. एफ. 01/04/2013 ईंधन और डॉलर की वर्तमान दरों पर विचार करते हुए दिनांकित 21/03/2013 पत्र में प्रस्तावित आपके सूत्र के अनुसार। इसे अभिलेखों के लिए नोट किया जा सकता है और आपकी शक्ति में शामिल किया जा सकता है। बिल। संशोधित निर्धारित दर 1 अप्रैल 2013 से लागू होगी।

6 ' आर. एल. एन. जी. ', संक्षेप में।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.3. 2 . हालाँकि, 30.04.2013 पर दावेदार ने स्पष्टीकरण माँगा।

बिजली की आपूर्ति के लिए देय सूत्र-आधारित शुल्क के संबंध में सरकार से, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शब्दों में: -

“ 1. हमारे दिनांकित प्रस्ताव में उल्लिखित मूल्य के संबंध में

प्रचलित आर. एल. एन. जी. मूल्य (\$17.2/एम. एम. बी. टी. यू.) और आई. एन. आर./यू. एस. डी. विनिमय दर (1 \$= 54 रुपये) और इसलिए निश्चित नहीं है। वही अलग होगा।

बाजार में ईंधन की कीमत और INR/USD के आधार पर विनिमय दर "।

4.3. 3 . यह दावेदार का मामला रहा है कि शुरू में,

गोवा सरकार प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर सहमत हो गई, लेकिन जब यह स्पष्ट किया गया कि कीमत तय नहीं की जाएगी, तो सरकार ईंधन और डॉलर की मौजूदा दरों को देखते हुए इसे खरीदने के लिए सहमत हो गई।

पी. पी. ए. की समाप्ति तक, जबकि यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए, दावेदार द्वारा उठाए गए बिलों में ईंधन और डॉलर की कीमत दिखाने वाले दस्तावेजों को शामिल किया जाए। इस संबंध में, दावेदार द्वारा मुख्य विद्युत अभियंता से दिनांक 23.05.2013 पर प्राप्त एक संचार पर भरोसा किया गया है। इसकी प्रासंगिकता के लिए, यह संचार दिनांकित 23.05.2013 है।

विस्तार से, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

" गोवा सरकार

विद्युत विभाग

मुख्य विद्युत इंजीनियर का कार्यालय

संख्या 20/3/सी. ई. ई./टक/13-14/824

तारीख:

23.05.2013

को,

एम/एस। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,

गोवा पावर स्टेशन,

ऑप. सेंकोले औद्योगिक संपदा,

ज़ुरीनगर, गोवा-403 726

उप: आर. एल. एन. जी. पर बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव

यह कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री के साथ संलग्न एक प्रति,
गोवा राज्य और अन्य।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

साहब,

आपके प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपके सूत्रों के अनुसार बिजली की खरीद जारी रखने का फैसला किया है। मौजूदा पी. पी. ए. की समाप्ति तक ईंधन और डॉलर की प्रचलित दरों पर विचार करते हुए दिनांकित 21.03.2013 पत्र में प्रस्तावित। इसे अभिलेखों के लिए नोट किया जा सकता है और आपकी शक्ति में शामिल किया जा सकता है।

ईंधन और डॉलर की कीमतों के उचित दस्तावेजों के साथ बिल

आप

की वफादारी से

एसडी /

(एस.

लक्ष्मीनाथ)

मुख्य विद्युत अभियंता "

4.3. 4 . दावेदार का यह भी मामला रहा है कि वास्तव में,

गोवा राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने उतार-चढ़ाव वाले मूल्य पर बिजली खरीदने के निर्णय को मंजूरी दी।

4.4 . दावेदार की शिकायत रही है कि उसके मासिक चालान

मार्च 2013 तक भुगतान किया गया था और अप्रैल 2013 के लिए मासिक चालान का आंशिक भुगतान किया गया था; लेकिन, मई 2013 के बाद से, इसके चालान का भुगतान नहीं किया गया था। दावेदार के अवैतनिक चालान के संबंध में, आंशिक रूप से अप्रैल 2013 के लिए और उसके बाद मई 2013 से अप्रैल 2014 तक (जिसके बाद संयंत्र को बंद कर दिया गया था), पक्षों के बीच कई संचारों का आदान-प्रदान किया गया और दावेदार ने संशोधित चालान प्रस्तुत किए लेकिन दावेदार की शिकायत का समाधान नहीं हुआ।

4.5 . 19.05.2015 पर, दावेदार ने संयुक्त के समक्ष एक याचिका दायर की

अपने बकाया की वसूली के लिए विद्युत नियामक आयोग। राज्य ने जे. ई. आर. सी. के समक्ष प्रस्तुत किया कि विवादों पर निर्णय लेने के लिए पी. पी. ए. के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाए। 11.12.2015 पर, JERC, के आधार पर

दोनों पक्षों के समझौते ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (च) के तहत अपनी शक्तियों के अनुसरण में विवादों को एकमात्र मध्यस्थ श्री न्यायमूर्ति बी. पी. सिंह (इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) को भेज दिया। मध्यस्थता

इस संदर्भ के तहत कार्यवाही ने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

7 'जे. ई. आर. सी. ', संक्षेप में।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता कार्यवाही और पुरस्कार

5. दावा, जवाब और जवाबी दावा, प्रतिदावे, प्रतिदावे, प्रतिदावे में संशोधन, विभिन्न आवेदनों को दाखिल करने और लिखित प्रस्तुतियों के साथ मध्यस्थता की लंबी कार्यवाही के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अंततः 16.02.2018 दिनांकित पुरस्कार पारित किया, जिसके तहत उसने राज्य को दावेदार को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 278.29 एक करोड़ रुपये (मूल राशि) ब्याज के साथ 31.10.2017 तक की अवधि के लिए; पुरस्कार की तारीख से राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 31.10.2017 से आगे ब्याज का भुगतान करने के लिए

प्रभावी भुगतान/प्राप्ति तक अधिनिर्णय की तारीख तक ब्याज; और आगे स्पष्ट किया कि यदि गैर-दावेदार ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान उस तारीख से दो महीने के भीतर करेगा। पुरस्कार की तारीख के बाद ब्याज के भुगतान के लिए यह उत्तरदायी नहीं होगा।

5.1 . हम मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को, प्रासंगिक सीमा तक, उचित समय पर आगे देखेंगे। लेकिन लेने के लिए

इस बात को समझने के लिए कि विवाद के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को क्या प्रस्तुत किया गया था और निर्धारण के लिए किन भौतिक बिंदुओं की आवश्यकता थी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि पक्षों ने संयुक्त रूप से उन मुद्दों को तैयार किया जिन पर

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देना आवश्यक था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित शब्दों में इन पर विधिवत ध्यान दिया गया था:

" 34. दावेदार को प्रत्यर्थी द्वारा देय दावा राशि की गणना पर उनके द्वारा प्रस्तुत संयुक्त बयान में पक्षों ने स्वयं उन मुद्दों को संक्षिप्त रूप से तैयार किया है जिन पर इस न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:

क) प्रत्यर्थी का तर्क है कि बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के आधार पर सितंबर 2000 से पीपीए की समाप्ति तक, यानी 13 अगस्त, 2014 तक निर्धारित क्षमता को कम करने की आवश्यकता है।

अपनी दलीलों के दौरान प्रत्यर्थी।

बी) जनवरी, 2009 से 13 अगस्त 2014 तक ईंधन लागत (परिवर्तनीय शुल्क) पर पहुंचने के लिए टैरिफ हीट रेट की गणना में सप्ताह के दिनों के लिए दैनिक आधार पर 12 घंटे के लिए 4 मेगावाट के क्रेडिट के लिए प्रतिवादी का दावा। प्रत्यर्थी ने 2 जनवरी, 2009 और 19 जनवरी, 2009 के पत्रों का उल्लेख करते हुए यह दावा किया है।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ग) प्रत्यर्थी का तर्क कि दावेदार ईंधन मूल्य की एक निश्चित दर और बिजली की आपूर्ति के लिए अमेरिकी डॉलर से आई. एन. आर. के संदर्भ में विनिमय की एक निश्चित दर के आधार पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था।

जून, 2013 से आर. एल. एन. जी. का ईंधन के रूप में उपयोग करना;

घ) दावेदार का दावा कि वह जून 2013 से आर. एल. एन. जी. का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति के लिए ईंधन सुविधा शुल्क का हकदार है, और

ई) प्रत्यर्थी का तर्क है कि उसके द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का समर्थन करें।

मई, 2014 से 13 अगस्त, 2014 तक यह 1.25 करोड़ रुपये था। 3.78 / kWh, उत्तरदाता द्वारा अपने दिनांकित पत्र में निर्दिष्ट दर होने के नाते

18 सितंबर, 2014 "।

5.2 . उपर्युक्त पाँच मुद्दों में से चार का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार के पक्ष में किया गया था (सिवाय इसके कि उनसे संबंधित

त्वरण शुल्क)। पक्षों ने निष्कर्षों के संदर्भ में देय राशि पर पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्प भी प्रस्तुत किए। एनजी ने इन विकल्पों की जांच की और अपने निष्कर्षों के संदर्भ में,

रिबुनल ने निम्नलिखित शब्दों में पुरस्कार दिया: -

“ 77. इस न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दावेदार के पक्ष में चार मुद्दों और प्रतिवादी के पक्ष में एक मुद्दे का फैसला किया है। उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए आकर्षित परिदृश्य परिदृश्य 22 है। तदनुसार, दावेदार रुपये की राशि का हकदार होगा। 119.32 मूल राशि के रूप में करोड़ और 31.10.2017 तक की अवधि के लिए ब्याज के रूप में करोड़ रुपये की राशि कुल रु। 278.29 करोड़। 31 अक्टूबर 2017 के बाद की अवधि के लिए, दावेदार उसी दर पर गणना किए गए ब्याज का हकदार होगा जो उस तारीख से पहले की अवधि के लिए, पुरस्कार की तारीख तक है। दावेदार पुरस्कार की तारीख से भुगतान की वास्तविक तिथि तक उपरोक्त राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी हकदार होगा।

ब्याज के साथ दी गई पूरी राशि। यदि ब्याज के साथ दी गई राशि का पूरा भुगतान पुरस्कार की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी पुरस्कार की तारीख के बाद की किसी भी अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अन्यथा, वह पुरस्कार की तारीख से पूर्ण भुगतान/प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में न्यायाधिकरण

निम्नलिखित करता है।

8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार

1. प्रत्यर्थी दावेदार को रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 278.29 मूल राशि के भुगतान के माध्यम से करोड़

31 अक्टूबर, 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज।

2. प्रत्यर्थी 31 अक्टूबर, 2017 से पुरस्कार की तारीख तक की अवधि के लिए उपरोक्त राशि पर दावेदार को ब्याज का भुगतान करेगा, जिसकी गणना 31 अक्टूबर, 2017 से पहले की अवधि के लिए उसी दर पर की जाएगी।

3. प्रत्यर्थी 31 अक्टूबर, 2017 को देय ब्याज के साथ दी गई कुल राशि पर दावेदार को पुरस्कार की तारीख से राशि के पूर्ण भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

पुरस्कार का भुगतान/प्राप्ति की जाती है।

4. बशर्ते कि, यदि प्रत्यर्थी दावेदार को पुरस्कार की तारीख से दो महीने के भीतर दिए गए ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करता है, तो वह इसके लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पुरस्कार की तारीख के बाद की अवधि।

5. पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

आगे बढ़ रहा है "।

अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती

6. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी

ई वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत राज्य। पक्षकारों की ओर से विभिन्न प्रकार की दलीलों का आग्रह किया गया था न्यायालय द्वारा विचार किए जाने और संबंधित बिंदुओं का उत्तर दावेदार के पक्ष में दिया गया और इस प्रकार, धारा 34 के तहत अभियोग को अस्वीकार करते हुए पुरस्कार को बरकरार रखा गया।

6.1 . वाणिज्यिक यू. आर. टी. की प्रासंगिक टिप्पणियों और निष्कर्षों को, आवश्यक सीमा तक, इसके बाद में निर्दिष्ट किया जाएगा

उचित चरण। हालांकि, हम निर्धारण के लिए बिंदुओं को निकाल सकते हैं वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा प्रस्तुत और उनके उत्तर, जैसा कि दिनांक 12.09.2019 के विवादित निर्णय और आदेश में इंगित किया गया है, निम्नानुसार हैं: -

" 27. मेरे दृढ़ संकल्प के लिए निम्नलिखित बिंदु उठते हैं:

एलिगेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

श्री. नहीं।

अंक

निष्कर्ष

1

क्या जी. ओ. जी. ने सकारात्मक के लिए सहमति व्यक्त की थी
डॉलर की दर में उतार-चढ़ाव?

क्या जी. ओ. जी. सकारात्मक के बारे में जानता था

2

और ईंधन आपूर्तिकर्ता?
चाहे सकारात्मक में शुल्क की अनुपस्थिति में

3

दावेदार द्वारा दायर याचिका,

दावेदार राशि का दावा कर सकता है
जीओजी?

चाहे एल. डी. मध्यस्थ को नकारात्मक होना चाहिए

4

एक विशेषज्ञ नियुक्त किया है

और

सुनिश्चित करें

शुद्धता

14.08.1999 से दावेदार और

विशेषज्ञ को प्रस्तुत करने के लिए बुलाना

रिपोर्ट करें?

क्या मध्यस्थता कार्यवाही नकारात्मक में है

5

खराब हैं क्योंकि कोई आदेश नहीं है

द्वारा दायर आवेदन पर पारित किया गया

30.03.2016 पर जी. ओ. जी. कॉल कर रहा है

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए दावेदार।

क्या नकारात्मक द्वारा दिया गया ब्याज

6

एल. डी. मध्यस्थ अत्यधिक है और

पी. पी. ए. के खिलाफ?

नकारात्मक में

7

मध्यस्थ कि 3.78 प्रति इकाई एक था

बैक-अप की आपूर्ति के लिए निश्चित राशि

जी. ओ. जी. द्वारा दावेदार को शक्ति है

पी. पी. ए?

क्या दावेदार नकारात्मक में शुल्क नहीं लगा सकता है

8

4 मेगावाट पर परिवर्तनीय शुल्क काटा गया

19 मेगावाट की निर्धारित क्षमता से?

नकारात्मक में

9

इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि

दावेदार ने विचार नहीं किया

घटाना?

10

मनमाना और विकृत और पारित

प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत

न्याय और इसलिए जनता के खिलाफ

नीति?

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील

7. वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.09.2019 के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य ने वाणिज्यिक अपील सं.

12 बॉम्बे, गोवा पीठ में उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत 2019 की धारा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और दिनांक 08.03.2021 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और इस प्रकार, प्रश्नगत पुरस्कार में निष्कर्षों के पर्याप्त और भौतिक भागों को उलट दिया गया है। 7.1 . पुनः, हम उचित स्तर पर उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्षों का उल्लेख करेंगे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उठाए गए बिंदुओं को इंगित करने के लिए।

विरोध में, निम्नलिखित निष्कर्षण उपयुक्त होगा: -

" 39. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमने अभिलेख की सामग्री पर भी विचार किया है, जिसमें विवादित पुरस्कार के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित निर्णय और आदेश भी शामिल हैं। प्रतिद्वंद्वी विवादों के आधार पर, अब हमारे दृढ़ संकल्प के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

(ए) धारा 34 के प्रावधानों का दायरा

मध्यस्थता अधिनियम (2017 में संशोधित)।

(ख) क्या अपीलार्थी ने उल्लंघन का मामला बनाया है।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक न्याय का

विवादित पुरस्कार में हस्तक्षेप की गारंटी?

(ग) क्या अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है कि परिवर्तनीय शुल्क के पहलू पर विवादित पुरस्कार रु। 24.66

करोड़ रुपये अलग रखने की आवश्यकता है?

(घ) क्या अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है कि रुपये के लिए अवमूल्यन के पहलू पर विवादित पुरस्कार। 18.53 करोड़

अलग करने की आवश्यकता है?

(ई) क्या अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है कि 4 मेगावाट पर परिवर्तनीय शुल्क के पहलू पर विवादित निर्णय

बिजली जिसका रुपये में व्यापार करने की अनुमति थी। 3.94 करोड़ रुपये अलग रखने की आवश्यकता है?

(च) क्या अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है कि रुपये के लिए नेट आउट करने के पहलू पर विवादित पुरस्कार। 2.36 करोड़

अलग करने की आवश्यकता है?

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(जी) क्या विवादित पुरस्कार देने तक की अवधि के लिए ब्याज का पुरस्कार और साथ ही पुरस्कार के बाद की अवधि,

हस्तक्षेप का आदेश देता है?

(ज) क्या विवादित पुरस्कार की अनुसूची 2 और 3 में की गई गणनाएं प्रत्यक्ष रूप से गलत हैं और बिना इसके की गई थीं।

अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान करना?

(I) क्या विवादित निर्णय और आदेश

वाणिज्यिक न्यायालय ने विवादित पुरस्कार को बरकरार रखा है

क्या यह गलत लगता है और हस्तक्षेप की आवश्यकता है? "

7.2 . जहाँ तक उपरोक्त बिंदु (ए) का संबंध है, उच्च न्यायालय ने हालांकि सांगयोंग इंजीनियरिंग के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया है।

और निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम। एनएचएआई: (2019) 15 एस. सी. सी. 131, जिसमें 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी निर्णय को चुनौती देने से निपटने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उसके बाद, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विश्लेषण का उल्लेख करना उचित समझा गया और विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय के कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, कहा गया कि प्रस्तुतियों का मूल्यांकन इस प्रकार बताए गए सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाएगा। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने बिंदु (बी) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया और कार्यवाही के रिकॉर्ड के संदर्भ में ऐसी सभी दलीलों को खारिज कर दिया। पक्षकारों की दलीलें और साक्ष्य। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इन दावों के संबंध में पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया

उपरोक्त बिंदु (सी), (डी), (ई) और (एफ)। बेशक, बिंदु (जी) पर, पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के पुरस्कार के संबंध में और

जिस अवधि के दौरान मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन फिर, वेदांता लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। शेनझेन शेडोंग परमाणु ऊर्जा निर्माण कंपनी लिमिटेड: (2019) 11 एस. सी. सी. 465, इस पर विचार किया

ब्याज की दर को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 10 प्रतिशत करना उचित है। बिंदु (एच) में, उच्च न्यायालय ने अनुसूची 2 और 3 के रूप में पुरस्कार से जुड़ी गणनाओं में कोई गलती नहीं पाई, लेकिन बिंदु (आई) में कहा गया कि वाणिज्यिक न्यायालय ने केवल पक्षों की प्रस्तुतियों का सारांश दिया और उठाए गए तर्कों पर स्वतंत्र रूप से विचार किए बिना पुरस्कार का संक्षिप्त संदर्भ दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार, यह अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन का निपटारा करने का संतोषजनक तरीका नहीं था। 1996 का अधिनियम।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.3 . उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आश्वासनों और निर्देशों के साथ इस मामले पर निष्कर्ष निकाला: -

" 195. उपरोक्त सभी कारणों से, हम आंशिक रूप से इस अपील की अनुमति देते हैं।

और विवादित निर्णय और आदेश दोनों के साथ-साथ परिवर्तनीय शुल्क (रु। 24.66 करोड़ लगभग), डाउनरेटिंग (रु। 18.53 करोड़ लगभग), 4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क (रु। लगभग 3 करोड़ 94 लाख), और कुल आय (रु। लगभग 2.36 करोड़)। हम अधिनिर्णय की तारीख से निर्धारित राशि के भुगतान की तारीख तक देय ब्याज दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर देते हैं। बाकी सब

हालाँकि, विवादित पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

196. चूँकि हमने सारांश के लिए चुनौती को अस्वीकार कर दिया है

आक्षेपित पुरस्कार की अनुसूची 2 में गणना, 4 मेगावाट बिजली, ईंधन सूत्र, सुविधा ईंधन शुल्क, और अपीलार्थी के पक्ष में नेट आउट करने के मुद्दों को रखने के बाद भी, अपीलार्थी अभी भी देय है और मूल राशि रु। 70.58 करोड़ रुपये ब्याज घटक के साथ जिसमें हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। यह राशि रुपये में आती है। 151.97 31.10.2017 के रूप में करोड़। इस राशि पर रु। 151.97 करोड़, अपीलार्थी 31.10.2017 से पुरस्कार की तारीख यानी 16.2.2018 तक की अवधि के लिए अनुमोदित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके बाद, तथापि, अपीलार्थी को अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

उत्तरदाता को राशि। 197. अपीलार्थी ने पहले ही रुपये की राशि जमा कर दी थी। 25 वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष स्थगन की शर्त के रूप में करोड़

विवादित पुरस्कार का निष्पादन। इसके बाद, अपीलार्थी ने रुपये की एक और राशि जमा की। 94 हमारे दिनांकित 8.11.2019 आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय में करोड़। प्रत्यर्थी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करके इन दोनों राशियों को निकालने की अनुमति दी गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंक। प्रत्यर्थी को इस वाणिज्यिक अपील के निपटारे तक ऐसी बैंक गारंटी को जीवित रखने का निर्देश दिया गया था

और उसके बाद 15 दिनों के लिए।

198. हालाँकि हमने इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि प्रतिवादी को उसके द्वारा निकाली गई राशि का कोई भी हिस्सा वापस लाना पड़ सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी इस स्थिति का आकलन करता है और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 14 दिनों के भीतर इस न्यायालय में ऐसी राशि, यदि कोई हो, जमा करता है।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आज। केवल अगर कोई राशि वापस नहीं लानी है, तो उत्तरदाता को बैंक गारंटी को 15 दिनों से अधिक समय तक जीवित रखने की आवश्यकता नहीं है। आज।

199. इसके अलावा, यदि इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति देने वाले हमारे आदेश के बावजूद, अपीलकर्ता अभी भी देय है और प्रत्यर्थी को उन राशियों से अधिक राशि का भुगतान करने योग्य है जो प्रत्यर्थी ने पहले ही बैंक गारंटी के खिलाफ वापस ले ली है, तो जाहिर है, प्रत्यर्थी को बैंक गारंटी को 15 दिनों से अधिक समय तक जीवित रखने की आवश्यकता नहीं है।

आज। अपीलार्थी तब आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में शेष राशि जमा करेगा। एक बार जमा हो जाने के बाद प्रत्यर्थी को ऐसी राशि निकालने की स्वतंत्रता होगी।

200. उपरोक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है। वहाँ

लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दावेदार ने उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को इस हद तक चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि

पुरस्कार को आंशिक रूप से अलग करता है। दूसरी ओर, गोवा राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले को सीमित चुनौती दी है। हम कर सकते हैं पक्षों की ओर से आग्रह की गई प्रमुख दलीलों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

9. दावेदार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पराग पी. त्रिपाठी ने इसे चुनौती देते हुए कई तरह की दलीलें दी हैं।

विवादित निर्णय और दिनांकित 08.03.2021 आदेश का हिस्सा जिसके तहत, विचाराधीन पुरस्कार के महत्वपूर्ण हिस्से को उच्च न्यायालय द्वारा पलट दिया गया है।

9.1 . शुरुआत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप का दायरा सीमित है और

इसकी धारा 34 में उल्लिखित आधारों तक ही सीमित है और यदि मध्यस्थ का दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, तो न्यायालय मध्यस्थ के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसे प्रतिस्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रावधानों के तहत साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन या गुण-दोष पर समीक्षा की अनुमति नहीं है। जब तक कि पुरस्कार को 'भारत की सार्वजनिक नीति' के साथ टकराव में नहीं दिखाया जाता है या 'पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता' द्वारा दूषित नहीं किया जाता है।

9.2 . इस निवेदन के संबंध में कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 26 के तहत विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए राज्य के आवेदन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, विद्वान वरिष्ठ वकील [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 51 और 52 में उल्लेख किया था कि विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग करने वाली प्रार्थना को राज्य द्वारा ही हटा दिया गया था। इसके अलावा, राज्य ने अपने जवाबी दावे की अस्वीकृति को कभी चुनौती नहीं दी और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से राशि की गणना की गई।

9.3 . जहां तक परिवर्तनीय शुल्कों का संबंध है, लगभग रु. 24.66 करोड़, दावेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तथ्य के स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि वैकल्पिक ईंधन आर. एल. एन. जी. का उपयोग करके बिजली की बिक्री निश्चित मूल्य पर नहीं होगी और यह अमेरिकी डॉलर और ईंधन की उतार-चढ़ाव वाली कीमत पर आधारित होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि पीपीए के कुछ खंडों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था, और उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने गैर-मध्यस्थता के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर विचार नहीं किया था।

विद्वान वरिष्ठ वकील, उच्च न्यायालय ने एक अप्रयोज्य खंड लागू किया, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त मूल्य प्रमाण पत्र और डॉलर दर सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को चालान के साथ अग्रेषित किया गया था। इसके अलावा, गोवा सरकार ने सत्ता पर कब्जा करना जारी रखा बिना किसी विवाद या आपत्ति के दावेदार से। अन्यथा भी, गोवा सरकार द्वारा समकालीन रूप से कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, और खंड 12.1 का कथित गैर-अनुपालन। 4 . 12. 1 तक। 7 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पहली बार प्रतिवाद में उठाया गया था।

9.4 . लगभग रु. की कटौती राशि के संबंध में। 18.53 विद्वान वरिष्ठ वकील ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष गोवा सरकार के इस तर्क को दोहराया है कि रेटेड क्षमता की आवश्यकता थी

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना के आधार पर सितंबर 2000 से 13.08.2014 (पी. पी. ए. की समाप्ति की तारीख) तक कम किया जाएगा। विद्वान वकील ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की टिप्पणियों पर भरोसा करके इसका विरोध किया है कि पीपीए में बाद के संशोधन को देखते हुए डाउनरेटिंग का मुद्दा अप्रासंगिक था।

8 ' एफ. एस. सी. ', संक्षेप में।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

मार्च 2013 तक गोवा सरकार और अप्रैल 2013 का एक हिस्सा। यह. यह भी माना गया कि क्षमता को कम करने के इस मुद्दे को पार्टियों द्वारा पहले ही सुलझा लिए जाने के बाद फिर से सक्रिय नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने गलती से एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ा है

ओ. ई. एम. की सिफारिश प्रस्तुत करने में विफलता के कारण दावेदार के खिलाफ निष्कर्ष और गलती से प्रक्रिया में प्रवेश किया है

बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.04.2007 की व्याख्या। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हुए वरिष्ठ वकील का अध्ययन किया। लिमिटेड वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड : (2022) 1 एस. सी. सी. 131 और हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड बनाम कंधारी बेवरेजेस लिमिटेड : (2022) 3 एस. सी. सी. 237 ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था।

9.5 . 4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क के सवाल के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा था -

क्या गोवा सरकार जनवरी, 2009 से 30.08.2014 तक ईंधन लागत परिवर्तनीय शुल्क पर पहुंचने के लिए शुल्क ताप दर की गणना में 4 मेगावाट के लिए क्रेडिट का दावा करने में उचित थी। यह दावा सरकार द्वारा 02.01.2009 और 19.01.2009 दिनांकित पत्रों के संदर्भ में किया गया था। यह संतोषजनक है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त पत्रों सहित साक्ष्यों की सराहना करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि गोवा सरकार को अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली इस 4 मेगावाट बिजली के संबंध में केवल निश्चित लागत के भुगतान से छूट दी गई थी और 19.01.2009 दिनांकित उक्त पत्र ने किसी भी तरह से प्रतिबद्ध बिजली को प्रभावित नहीं किया।

9 'ओ. ई. एम.', संक्षेप में।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावेदार द्वारा सरकार को आपूर्ति। इसके अलावा, सरकार ने भविष्य में उक्त 4 मेगावाट बिजली लेने के अपने अधिकार को बरकरार रखा था और पी. पी. ए. के सभी नियम और शर्तें समान रहीं; और उन्हें आपूर्ति के लिए सरकार को बिल किए गए परिवर्तनीय शुल्क पी. पी. ए. के अनुसार थे। विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने गलती से

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने के लिए पत्रों की सराहना की।

9.6 . निर्धारित कटौती (जब संयंत्र मई और अगस्त, 2014 के बीच बंद कर दिया गया था) के मामले में दावेदार को सरकार द्वारा बैकअप बिजली की आपूर्ति से संबंधित मुद्दे के संबंध में, सरकार ने रुपये की स्वीकृत दर का 125 गुना अपनी पात्रता का दावा किया। 3.78 प्रति

इकाई जिस पर दिनांकित 18.09.2014 पत्र में सहमति व्यक्त की गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सही निष्कर्ष पर आया है

कि प्रति इकाई दर एक निश्चित राशि थी क्योंकि ऊर्जा की औसत लागत का निर्धारण अप्रासंगिक हो गया था, दिनांक 13.08.2014 और 18.09.2014 के कार्यालय ज्ञापनों पर भरोसा करके। विद्वान वकील के अनुसार, यह फिर से केवल उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पुनः प्रशंसा का विषय रहा है।

9.7 . अनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के आधार पर पोस्ट-अवार्ड पर ब्याज को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करने के संबंध में

वेदांत लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि पुरस्कार के बाद का ब्याज इसके तहत दिया गया था

1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (बी) और दावेदार ने यह संकेत देते हुए बयान सौंपा था कि प्रमुख ऋण दर लगभग 13 प्रतिशत प्रति वर्ष और उससे अधिक थी और इसलिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित था।

दावेदार की ओर से और तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने पेटेंट अवैधताओं से पीड़ित प्रश्न में पुरस्कार में सही हस्तक्षेप किया है। विद्वान महान्यायवादी ने दिनांकित 08.03.2021 के विवादित निर्णय और आदेश में टिप्पणियों और निष्कर्षों पर भी सवाल उठाया है

जिस हद तक राज्य की प्रस्तुतियों को अस्वीकार या खारिज कर दिया गया है।

10.1 . विद्वान महान्यायवादी ने धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के दायरे पर इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया है। सांगयोंग इंजीनियरिंग (ऊपर) सहित 1996 का अधिनियम;

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड: (2019) 4 एस. सी. सी. 163; और पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स (पी) लिमिटेड v. वी. ओ. चिदम्बरनार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का न्यासी मंडल।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पोर्ट ट्रस्ट तृतीकोरिन और अन्या : (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 508। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह दो प्रशंसनीय विचारों का मामला नहीं है मध्यस्थ न्यायाधिकरण लेकिन संबंधित संविदात्मक खंडों का विज्ञापन न करने और उन पर विचार न करने का मामला जिसके कारण पेटेंट अवैध हो जाता है। के अनुसार

विद्वान महान्यायवादी को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पूरे मामले को पूरी तरह से गलत कोण से संपर्क किया था; और जब मध्यस्थ ने गलत प्रश्नों पर ध्यान दिया, तो परिणाम गलत उत्तरों का रहा है। विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय सही है इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थता पर निर्णय नहीं दिया, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आदेश में हस्तक्षेप किया।

मूल प्रश्न की जांच करें कि क्या इस तरह के पत्राचार का अनुबंध की शर्तों में भिन्नता का प्रभाव था और क्या ऐसा था पत्राचार ने अनुबंध के मूल सिद्धांतों को बदल दिया। विद्वान।

महान्यायवादी ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों पर विचार नहीं किया है और यह पेटेंट अवैधता का मामला था। इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया गया है

इस संबंध में, अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य और अन्या वी. साल उद्योग प्रा. लि. : (2022) 2 एस. सी. सी. 275 और एसोसिएट बिल्डर्स बनामा दिल्ली विकास प्राधिकरण: (2015) 3 एस. सी. सी. 49. इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह पुरस्कार पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है।

1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) के तहत क्योंकि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों के बीच अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकता है और महत्वपूर्ण साक्ष्य की अज्ञानता में पुरस्कार दिया गया था। 10.3 . जहां तक प्रक्रियात्मक पहलुओं का संबंध है, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

न्याय क्योंकि अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन का मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा नहीं किया गया था, हालाँकि न्यायाधिकरण द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि इसका निर्णय इस प्रकार किया जाएगा -

उचित समय। यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने में विफलता के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 18 का उल्लंघन करते हुए राज्य को अपना मामला पेश करने के लिए समान अवसर से वंचित कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 26 के तहत एक विशेषज्ञ की नियुक्ति के पीछे के उद्देश्य और इरादे की अनदेखी की।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.3. 1 . राज्य द्वारा एक अन्य आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावेदार द्वारा 13 दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, जिसमें प्रत्येक ईंधन आपूर्ति अनुबंध की बातचीत में प्रगति और विकास का मसौदा, ईंधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठकों के कार्यवृत्त के साथ-साथ शुद्ध उत्पादन क्षमता को कम करने के संबंध में ओ. ई. एम. की सिफारिशें शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस आवेदन का भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा नहीं किया गया था। विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करेंगे कि दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने से राज्य को गंभीर रूप से पूर्वाग्रह हुआ है क्योंकि कुछ ओ. ई. एम. नियमावली जैसे दस्तावेज इसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे; और यह

दावेदार पर अपने अनन्य कब्जे में दस्तावेजों को पेश करने का दायित्व था और इन दस्तावेजों को पेश करने के अभाव में दावेदार के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

10.3. 2 . यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के राज्य के अनुरोध को मंजूरी नहीं दी गई थी

दावेदार द्वारा अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में रखे जाने के बाद भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण। केवल इसलिए कि एक संयुक्त अभ्यास किया गया था और पार्टियों द्वारा गणना के 24 क्रमपरिवर्तन प्रस्तुत किए गए थे, किसी भी समय राज्य ने ब्याज या उसकी मात्रा के संबंध में अपने दावों को नहीं छोड़ा।

10.4 . परिवर्तनीय आरोपों के संबंध में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि पी. पी. ए. के खंड 12.4 से 12.7 की प्रयोज्यता नहीं थी।

पुरस्कार में विचार या चर्चा की गई। इन खंडों में एक सामग्री थी

रुपये का भुगतान करने के लिए गोवा सरकार के दायित्व के सवाल पर। 24.66 नाफ्था से आर. एल. एन. जी. में ईंधन में परिवर्तन से संबंधित परिवर्तनीय शुल्कों के कारण; और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला था कि उपरोक्त खंड तब लागू नहीं थे जब नाफ्था से आर. एन. एल. जी. में परिवर्तन किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि दावेदार ईंधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में सरकार को अद्यतन रखने और संभावित आपूर्तिकर्ताओं और अन्य मसौदों के साथ पत्राचार प्रदान करने के लिए बाध्य था। आई. डी. 1 दिनांकित पत्र में कहा गया है कि पी. पी. ए. के सभी नियम और शर्तें अप्रभावित रहने चाहिए और एफ. एस. सी. और विस्तृत चालानों को पेश न करने से सरकार से आपत्ति करने का अवसर छीन लिया गया। पी. पी. ए. की शर्तों के आलोक में, दावेदार का यह निवेदन कि सरकार डॉलर की दर और आर. एल. एन. जी. की दर को स्थिर नहीं कर सकती, अस्थिर होगा। इसके अलावा, यह कहना गलत होगा कि अगर ईंधन सुविधा शुल्क

यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को नहीं दिया गया होता, तो एफ. एस. सी. प्रदान करने की आवश्यकता को माफ कर दिया जाता।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

10.5 . रुपये की राशि को कम करने के संबंध में। 18.53 करोड़, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया

कि डाउनरेटिंग का मुद्दा 05.04.2007 पर पक्षों के बीच हल किया गया था और डाउनरेटिंग से संबंधित प्रासंगिक संविदात्मक प्रावधानों की सलाहना करने में विफल रहा। पी. पी. ए. के तहत परिभाषित 'संविदात्मक क्षमता' की परिभाषा के लिए आवश्यक था कि डाउनरेटिंग को ध्यान में रखा जाए, और इस परिभाषा को पूरक पी. पी. ए. द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। इसलिए, न्यायाधिकरण के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं था कि डाउनरेटिंग को मंजूरी दी गई थी। यह देखते हुए कि दावेदार ने ओ. ई. एम. सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की थीं, राज्य को डाउनरेटिंग की गणना करने के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना पर भरोसा करना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि ओ. ई. एम. सिफारिशों को प्रस्तुत करने में इस विफलता के लिए दावेदार के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होगी और दावेदार बाद में यह तर्क देने के लिए 08.11.2005 दिनांकित प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता था कि कोई गिरावट नहीं है।

डाउनरेटिंग की प्रयोज्यता को दूषित करते हुए ऐसा हुआ था। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांकित 08.11.2005 प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के बाद संयंत्र के क्षरण के बारे में निर्णायक और इसलिए, संविदात्मक शर्त को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अनुबंधित क्षमता में परिवर्तन के बावजूद अनुबंध के संदर्भ में डाउनरेटिंग को लागू करना होगा क्योंकि, यदि डाउनरेटिंग की अवधारणा निरर्थक हो गई होती, तो दावेदार ने इसे वर्ष 2007 में ही इंगित किया होता।

10.6 . जहां तक रुपये के पुरस्कार की बात है। 3.94 जाने-माने महान्यायवादी ने कहा है कि 4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रस्तुत किया कि केवल बिजली के संबंध में परिवर्तनीय शुल्क का भुगतान किया जाना था

वास्तव में खरीदा गया, जबकि निश्चित शुल्क वास्तविक खरीद की परवाह किए बिना देय थे क्योंकि बुनियादी ढांचे की लागतों के साथ कोई संबंध नहीं था। इस अंक पर विवाद यह रहा है कि वे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

बिजली के लिए परिवर्तनीय शुल्क जो उन्हें आपूर्ति नहीं किए गए थे, विशेष रूप से जब पक्ष भी उस संबंध में निश्चित शुल्क को माफ करने के लिए सहमत हुए थे। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 4 मेगावाट बिजली के लिए परिवर्तनीय शुल्क के लिए भुगतान का निर्देश देने में गलती की, जिसकी कभी आपूर्ति नहीं की गई थी

गोवा सरकार को। जब दावेदार को तीसरे पक्ष को बेचने की अनुमति दी गई थी, उस अवधि के लिए अनुबंधित क्षमता में 4 मेगावाट की कमी की गई थी और इसलिए, उस अवधि के लिए परिवर्तनीय शुल्कों का बिलिंग करते समय, अनुबंधित क्षमता को भी कम करना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि दावेदार द्वारा तीसरी इकाई को बेची गई इकाइयों पर सरकार से परिवर्तनीय शुल्क लिया गया है। पार्टियाँ। इसके परिणामस्वरूप दावेदार को दोहरा लाभ हुआ है, क्योंकि वह [2023] 8 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य को बिजली की आपूर्ति नहीं करने के बावजूद 4 मेगावाट बिजली के लिए परिवर्तनीय लागत की वसूली करने का हकदार है; और ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा 4 मेगावाट बिजली के लिए निश्चित शुल्क और परिवर्तनीय शुल्क दोनों के लिए क्षतिपूर्ति भी की जा रही है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दिनांकित 19.01.2009 पत्र पर भरोसा किया, जिसमें दावेदार को तीसरे पक्ष को 4 मेगावाट बिजली का व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह देखने में विफल रहा कि यह दावेदार द्वारा पिछले संचार के जवाब में था जिसमें, निश्चित शुल्क का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया था। इस प्रकार, 19.01.2009 दिनांकित पत्र को 4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क के भुगतान के लिए स्वीकृति के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इस संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निष्कर्ष विकृत था।

10.7 . विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने फिर से अनुबंध संबंधी खंडों को नजरअंदाज कर दिया है जो जाली को अनिवार्य करते हैं। रुपये की राशि में पुरस्कार देते समय। 2.36 एक करोड़। यह तर्क दिया गया है कि द्वितीय पूरक पी. पी. ए. के खंड 15 में यह प्रावधान किया गया है कि एक अनिर्धारित अवधि के दौरान सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी अतिरिक्त ऊर्जा

निकटवर्ती बिलिंग अवधि में प्रचलित दर पर शुद्ध ऊर्जा के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण खंड 15 के तहत अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए जाली की अनिवार्य प्रकृति पर ध्यान देने में विफल रहा है और पूरी तरह से दिनांकित 18.09.2014 दस्तावेज़ की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि रुपये की दर का निर्धारण। 3.78 प्रति इकाई नेट आउट की गणना के लिए आधार दर थी और इसे अनुबंध के उक्त प्रावधानों की छूट के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, दावेदार प्रासंगिक बिलिंग अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहा था, जिसके कारण आधार दर निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ी। दावेदार सरकार द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की गई इकाइयों के 125 गुना के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि दावेदार ने तर्क दिया कि वे केवल 1 इकाई वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वास्तव में, रुपये की आधार दर। 3.78 यह पिछली भुगतान दर की तुलना में बहुत कम थी, जो रु। 12.57 प्रति इकाई। किसी भी स्थिति में, पी. पी. ए. के खंड 23.1 के संदर्भ में दर की गणना से जाली को बाहर करने के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया था और सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी गई थी।

10.8 . अंत में, जहां तक ब्याज के सवाल का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए कोई ब्याज ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड देने का कोई कारण नहीं था।

बी. गोवा का राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पुरस्कार की तारीख से पहले क्योंकि विवाद में होने के कारण चालान का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि दावेदार बड़े हुए बिल ले रहा था; और जो राशि देय थी उसे दावेदार के लिए स्पष्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह गोवा सरकार को आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा था। इस तरह के दस्तावेज केवल मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान प्रदान किए गए थे और इस प्रकार, यदि ब्याज के लिए किसी भी राशि को देय और देय माना जाता था, तो यह उस तारीख से ही शुरू हो सकता था जब अंतिम राशि को स्पष्ट किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया है कि ब्याज के लिए संविदात्मक प्रावधान क्षेत्र में थे और अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के संबंध में त्याग किए जाने योग्य थे। हालाँकि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार के बाद के ब्याज को कम कर दिया, लेकिन केवल राशि में संशोधन किया। एनएचएआई बनाम पर भरोसा करके इसे आगे प्रस्तुत किया गया है। एम. हकीम: (2021) 9 एस. सी. सी. 1, कि इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार का संशोधन संभव नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायाधिकरण के ब्याज के अधिनिर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध होने के रूप में अलग किया जाना चाहिए था।

10.9 . सम्मानित राशि की गणना के संदर्भ में विद्वान महान्यायवादी द्वारा कुछ अन्य प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं।

यह तर्क दिया गया है कि पी. पी. ए. के अनुसार, दावेदार को पूर्वानुमान अवधि के अनुसार और उसके बाद प्रत्येक बाद के वित्तीय वर्ष के लिए अपने बिल जमा करने की आवश्यकता थी; हालाँकि, दावेदार ने इसके लिए बिल जमा किए।

शुल्क अवधि जिसके परिणामस्वरूप बिलों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कथित पारस्परिक आधार पर दी जाने वाली राशि की गणना की।

गणना की तालिका पर सहमति; हालाँकि, दावेदार द्वारा प्रदान की गई गणनाओं के सेट पर राज्य द्वारा विवाद किया गया था। न्यायाधिकरण ने इस निवेदन के लिए विज्ञापन नहीं दिया कि भुगतान की जाने वाली मूल राशि रु। 60.76 रुपये के विपरीत करोड़। 70.58 दावेदार द्वारा दावा किए गए करोड़। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, दावेदार ने अनुबंध पर अत्यधिक बिलिंग का सहारा लिया है और देय राशि को इस तथ्य के कारण स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि दावेदार ने दायित्व का पता लगाने के लिए तीसरे पक्ष को बेची गई बिजली का विवरण प्रदान नहीं किया था, और यह दस्तावेज केवल मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान प्रदान किया गया था।

11. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान

12. चूंकि वर्तमान अपील एक मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित है, जिसे धारा 34 के तहत और धारा [2023] 8 एस. सी. आर. के तहत अपील में चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1996 का अधिनियम; और प्रस्तुतियों की विविधता को देखते हुए,

1996 के अधिनियम की धारा 26, 28, 34 और 37 में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर उपयोगी रूप से ध्यान दें:

" 26. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विशेषज्ञ की नियुक्ति। - (1) जब तक कि

अन्यथा पक्षकारों द्वारा सहमत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कर सकता है

(अ)

विशिष्ट विषय पर रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त करें।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे, और

(ख) विशेषज्ञ को कोई प्रासंगिक जानकारी देने के लिए किसी पक्ष की आवश्यकता होती है।

उसके लिए प्रासंगिक दस्तावेज, सामान या अन्य संपत्ति निरीक्षण।

या यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे आवश्यक समझता है, तो विशेषज्ञ, अपनी लिखित या मौखिक रिपोर्ट देने के बाद, मौखिक रिपोर्ट में भाग लें।

उसे और पर गवाही देने के लिए विशेषज्ञ गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए मुद्दे पर बिंदु।

(3) जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, विशेषज्ञ,

एक पक्ष का अनुरोध, उस पक्ष को परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएँ

के कब्जे में सभी दस्तावेज, सामान या अन्य संपत्ति विशेषज्ञ जिसके साथ उन्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदान किया गया था।

28. विवाद के सार पर लागू नियम। - (1) कहाँ का

मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है -

(अ)

एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक के अलावा एक मध्यस्थता में

भारत में कुछ समय के लिए प्रभावी कानून;
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में,

(ख)

(i) मध्यस्थ न्यायाधिकरण में विवाद का फैसला करेगा

द्वारा निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार

विवाद के सार पर लागू होने वाले पक्षकार;

(ii) कानून या कानूनी पक्षों द्वारा कोई पदनाम
किसी दिए गए देश की प्रणाली का अर्थ तब तक लगाया जाएगा जब तक कि

अन्यथा व्यक्त किया गया, जैसा कि सीधे ELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
का उल्लेख है।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उस देश का मूल कानून और इसके संघर्ष के लिए नहीं

कानून के नियम;

((iii) खंड (क) के तहत कानून के किसी भी पदनाम में विफल होना।
पक्षकारों द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियमों को लागू करेगा

कानून के सभी को देखते हुए यह उचित मानता है
विवाद के आसपास की परिस्थितियाँ।

(2) माध्यस्थ न्यायाधिकरण पूर्व और निःशुल्क या के रूप में निर्णय लेगा। सौहार्दपूर्ण संयोजन
केवल तभी होगा जब पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से अधिकृत किया हो

ऐसा करने के लिए।

1 0 [(3) निर्णय लेते समय और निर्णय देते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण

सभी मामलों में अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा और

लेन-देन पर लागू व्यापार उपयोग।]

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। - (1) सहारा

एक मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ एक अदालत को केवल एक द्वारा किया जा सकता है उप के
अनुसार ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन

धारा (2) और उप-धारा (3)।

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

(क) आवेदन करने वाला पक्ष [आधार पर स्थापित करता है]

माध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख का कि]

((i) कोई दल किसी असमर्थता के अधीन था, या
((ii) मध्यस्थता समझौता कानून के तहत मान्य नहीं है।

जिन पक्षों ने इसके अधीन किया है या किसी भी मामले में विफल रहे हैं

उस पर संकेत, कुछ समय के लिए कानून के तहत

बल में; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को उचित रूप से नहीं दिया गया था।

मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना या

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा करने में असमर्थ था

अपना मामला प्रस्तुत करें; या

. 2016 के अधिनियम 3 द्वारा, एस। 14 , उप-धारा (3) (w.r.e.f) के लिए। 23-10-2015)। उप-खंड

प्रतिस्थापन के लिए, निम्नानुसार खड़ा था:

) सभी मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शर्तों के अनुसार निर्णय लेगा

लेन-देन करें और व्यापार के उन उपयोगों को ध्यान में रखें जो इसके लिए लागू होते हैं

एनसाक्शन "। .

एस. 2019 के अधिनियम 33, धारा 7 द्वारा, "प्रमाण प्रस्तुत करता है कि" [डब्ल्यू. ई. एफ. 30-8-2019,154 (ई), दिनांक 30 अगस्त, 2019 के माध्यम से]।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार किसी विवाद से संबंधित नहीं है।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर आने या न आने पर विचार किया गया है, या इसमें प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता:

बशर्ते कि, यदि मामलों पर निर्णय

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए गए मामलों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

मध्यस्थता को अलग रखा जा सकता है; या

(v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के साथ संघर्ष में न हो जिससे पक्षकार अवमूल्यन न कर सकें, या ऐसे समझौते में विफल न हो सकें।

इस भाग के अनुसार; या

अदालत ने पाया कि

(i) विवाद का विषय-मामला उस समय के लिए कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है।

बल में होना, या

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

भारत से।

एनीशन 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, केवल

((i) पुरस्कार देने के लिए प्रेरित या प्रभावित किया गया था -

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या धारा 75 का उल्लंघन था

या धारा 81; या

((ii) यह मौलिक नीति का उल्लंघन है।

भारतीय कानून; या

3 2016 का, सेका 18 (1) , स्पष्टीकरण के लिए (w.r.e.f। 23-10-2015)। प्रतिस्थापन, निम्नानुसार था:1. -उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्वारा यह किसी भी संदेह से बचा जा सकता है कि यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था तो कोई पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के साथ टकराव में है। एलिएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

((iii) यह नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

या न्याय।

स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।]

[(2 क) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार के सामने आने वाली पेटेंट अवैधता से पुरस्कार दूषित है:

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल आधार पर अलग नहीं रखा जाएगा

कानून के गलत अनुप्रयोग या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन द्वारा।]

धारा 33 के तहत उस तारीख से किया गया था, जिस दिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया था: बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक था

तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया, यह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

14 [(5) इस धारा के तहत एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और ऐसा आवेदन के साथ आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र दिया जाएगा जो उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करता है।

2016 के अधिनियम 3 द्वारा, एस। 18 (II) (w.r.e.f। 23-10-2015)। 2016 के अधिनियम 3 द्वारा, एस। 18 (III) (w.r.e.f। 23-10-2015)।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(6) इस धारा के तहत एक आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

वह तारीख जिस पर उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सूचना जारी की जाती है दूसरे पक्ष पर।]

37. अपील योग्य आदेश। - (1) 1 5 [किसी भी बात के बावजूद उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित, एक अपील]

निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से लेकर

मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय

आदेश पारित करने वाला न्यायालय, अर्थात्:

1 6 16 [(ए) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना;
(ख) धारा 9 के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना;

(ग) के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना

धारा 34।] (2) मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी।

(3) धारा 16 की; या (ख) धारा के तहत अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना।

17 .

(3) अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

इस धारा के तहत, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं लेगा

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

12.1 . पुरस्कार में ब्याज के संबंध में 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7)

यह भी उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है जो नीचे लिखा है:

" 31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु।

XXX

XXX

XXX

. 2019 के अधिनियम 33, धारा 8 द्वारा, एस. ओ. 3154 (ई) के माध्यम से "एक अपील" [डब्ल्यू. ई. एफ. 30-8-2019 के लिए,

30 अगस्त, 2019]।

. 2016 के अधिनियम 3 द्वारा, एस। 20 , खंड (ए) और (बी) (w.r.e.f के लिए 23-10-2015)। प्रतिस्थापन से पहले खंड 1 (बी) निम्नानुसार था:

क) धारा 9 के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना;

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना या अलग रखने से इनकार करना। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(7) (क) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, कहाँ और कहाँ

जहाँ तक एक मध्यस्थ पुरस्कार धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थ

न्यायाधिकरण उस राशि को शामिल कर सकता है जिसके लिए पुरस्कार दिया जाता है।

ब्याज, ऐसी दर पर जो उसे उचित लगे, समग्र रूप से या किसी भी रूप में

पैसे का हिस्सा, पूरी या बीच की अवधि के किसी भी हिस्से के लिए

जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को कार्रवाई की गई पुरस्कार दिया जाता है।

1 7 [(बी) एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि, जब तक कि

पुरस्कार अन्यथा निर्देशित करता है, प्रति दो की दर से ब्याज लेता है

प्रतिशत। तारीख को प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से अधिक

पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक।
स्पष्टीकरण। - "ब्याज की वर्तमान दर" पद होगा

वही अर्थ जो धारा 2 के खंड (बी) के तहत उसे सौंपा गया है

ब्याज अधिनियम, 1978 (1978 का 14)]

X

XX "

XXX

XXX

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने का दायरा
और अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का दायरा

13. आग्रह किए गए विवादों और उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए,

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने की गुंजाइश और 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की गुंजाइश पर पक्षों द्वारा उद्धृत कुछ प्रासंगिक निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान देना भी उचित होगा।

13.1 . एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने विभिन्न बातों पर ध्यान दिया

एसोसिएट बिल्डरों (ऊपर दिए गए) के मामले में निर्णय और धारा 34 के तहत हस्तक्षेप के सीमित दायरे को उजागर करना और 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की गुंजाइश को और कम करना, विशेष रूप से जब समवर्ती निष्कर्षों (मध्यस्थ और फिर न्यायालय के) से निपटना हो। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" 11. जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, स्थिति अच्छी है।

अब तक तय हो गया है कि न्यायालय मध्यस्थता पर अपील में नहीं बैठता है पुरस्कार और प्रदान किए गए सीमित आधार पर योग्यता पर हस्तक्षेप कर सकता है

17 उप. 2016 के अधिनियम 3 द्वारा, एस। 16 (i), खंड (b) (w.r.e.f के लिए 23-10-2015)। प्रतिस्थापन से पहले खंड (बी) निम्नानुसार था:

" (बी) एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि, जब तक कि पुरस्कार अन्यथा निर्देश नहीं देता है, की तारीख से अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा

भुगतान की तारीख तक पुरस्कार। "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 (2) (बी) (ii) के तहत अर्थात् यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। 2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय के फैसलों के माध्यम से स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारतीय कानून के हितों का उल्लंघन शामिल है।

भारत, न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष, और मध्यस्थता पुरस्कार में पेटेंट अवैधता का अस्तित्व। इसके अलावा, की अवधारणा

(1948) 1 के. बी. 223 (सी. ए.)] तर्कसंगतता। इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" को स्वयं का उल्लंघन माना गया है भारत का मूल कानून, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन।

12. यह केवल तभी है जब इनमें से एक शर्त को पूरा किया जाता है कि न्यायालय

धारा 34 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में धारा 34 (2) (बी) (ii) के गुणों की समीक्षा शामिल नहीं है।

विवाद, और उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब न्यायालय की अंतरात्मा हैरान हो जाती है, या जब अवैधता तुच्छ नहीं होती है, बल्कि मामले की जड़ तक जाती है। एक मध्यस्थता पुरस्कार हो सकता है

यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। (एसोसिएट बिल्डर्स बनाम देखें। डीडीए [एसोसिएट] बिल्डर्स बी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. बी.) 2047। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम भी देखें। सॉ पाइप्स लिमिटेड. [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 7057; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। मित्रों कोयला कार्बनीकरण [हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। फ्रेंड्स कोल कार्बोनाइजेशन, (2006) 4 एस. सी. सी. 445] और मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड [मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 1817)

13. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 34 में 2015 के संशोधन के बाद, उपरोक्त स्थिति कुछ हद तक संशोधित है। धारा 34 (2) में स्पष्टीकरण 1 को शामिल करने के अनुसरण में, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के दायरे को संशोधित किया गया है -

इस हद तक कि अब इसका अर्थ पुरस्कार देने में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अधिनियम की धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन है, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, और संघर्ष एलिएंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्याय या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ। इसके अलावा,

धारा 34 में उप-धारा (2-ए) जोड़ी गई है, जिसमें प्रावधान है कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में भारतीय जनता का उल्लंघन होता है। नीति में पेटेंट की अवैधता भी शामिल है जो इसके चेहरे पर दिखाई देती है

पुरस्कार। उसी के परंतुक में कहा गया है कि एक पुरस्कार केवल कानून के गलत आवेदन या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा।

14. जहाँ तक धारा 37 के अनुसार धारा 34 के तहत दिए गए आदेश में हस्तक्षेप का संबंध है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि

धारा 37 के तहत इस तरह का हस्तक्षेप इससे आगे नहीं जा सकता है।

धारा 34 के तहत निर्धारित प्रतिबंध। दूसरे शब्दों में, न्यायालय पुरस्कार के गुण-दोष का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकता है, और उसे केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 34 के तहत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा और धारा 37 के तहत अपील में अदालत द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की गई है, तो इस अदालत को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।

13.2 . सांगयोग इंजीनियरिंग (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में विस्तार से बताया है: -

" 37. जहाँ तक भारत में किए जाने वाले घरेलू पुरस्कारों की बात है,

संबंधित, एक अतिरिक्त आधार अब उप-धारा के तहत उपलब्ध है

(2 - ए), संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ा गया। यहाँ, पुरस्कार के चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, जिसे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से नहीं जुड़े कानून का उल्लंघन, पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है।

जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है।

38. दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन, जो कि एक अपीलीय न्यायालय को करने की अनुमति है, पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है

पुरस्कार के चेहरे पर।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 तथापि, एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] बना रहेगा, यदि कोई मध्यस्थ किसी निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और 1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है, जो निश्चित रूप से पुरस्कार के बावजूद एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा।

40. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 (3) में किया गया परिवर्तन वास्तव में एसोसिएट में पैरा 42.3 से 45 में बताए गए परिवर्तन का अनुसरण करता है। बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], अर्थात्, कि किसी अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है, जब तक कि मध्यस्थ

अनुबंध को इस तरह से समझता है कि कोई निष्पक्ष या निष्पक्ष नहीं है। तर्कसंगत व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। इसके अलावा, अगर मध्यस्थ बाहर भटकता है

अनुबंध और उन मामलों से संबंधित है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, वह प्रतिबद्ध है

अधिकार क्षेत्र की त्रुटि। चुनौती का यह आधार अब गिर जाएगा।

धारा 34 (2-ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर।

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो है

विकृत, जैसा कि एसोसिएट के पैरा 31 और 32 में समझा गया है बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष भी किसी भी साक्ष्य के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होगा क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा।

13.3 . अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती का सीमित दायरा

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में इस न्यायालय ने एक बार फिर इस पर प्रकाश डाला

इनल्स (उपरोक्त) और इस न्यायालय ने विशेष रूप से संबंधित परीक्षणों की व्याख्या की:

एलिअंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 43. इस प्रकार यह एक तय कानूनी स्थिति से अधिक प्रतीत होगी, कि धारा 34 के तहत एक आवेदन में, अदालत से अपील की अदालत के रूप में कार्य करने और साक्ष्य की पुनः साराहना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हस्तक्षेप का दायरा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए आधारों तक सीमित होगा। हस्तक्षेप तब उचित होगा जब पुरस्कार "भारत की सार्वजनिक नीति" का उल्लंघन करता है, जिसका अर्थ "भारतीय कानून की मौलिक नीति" माना गया है। पुरस्कार के गुण-दोष में हस्तक्षेप करने के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सिद्धांत

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित प्राकृतिक न्याय चुनौती का आधार बना रहेगा।

एक पुरस्कार। इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है, अब "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ टकराव के रूप में समझा जाना चाहिए। यह केवल ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार हैं जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं, जिन्हें उक्त आधार पर दरकिनार किया जा सकता है। एक पुरस्कार होगा पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग रखा जाएगा और इस तरह, जो मामले की जड़ों तक जाता है। हालांकि, कानून के केवल गलत अनुप्रयोग के संबंध में एक अवैधता हस्तक्षेप का आधार नहीं होगी। समान रूप से, पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

44. एक निर्णय जो विकृत है, हालांकि एक आधार नहीं होगा

"भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगी। हालांकि, बिना किसी सबूत के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण सबूत की अनदेखी करता है, विकृत और अनुचित होगा।

पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी।

45. विकृति की कसौटी को समझने के लिए यह भी उचित होगा

एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से पैराग्राफ 31 और 32 का उल्लेख करना, जो इस प्रकार है:

" 31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, महत्वपूर्ण है और इसके लिए कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह तय किया गया कानून है कि कहाँ:

(1) एक निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित होता है, या (ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण

इस निर्णय के लिए कुछ अप्रासंगिक को ध्यान में रखता है जो यह [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहुँचता है; या (iii) अपने निर्णय पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा करता है,

32. विकृति की एक अच्छी कार्यशील परीक्षा दो निर्णयों में निहित है। उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण V. गोपी

नाथ एंड संस [1992 सप (2) एस. सी. सी. 312], यह आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी. पी. 317 , पैरा 7)

“ 7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि अगर तथ्य की खोज की जाती है

प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करके या बाहर करके या इसमें शामिल करके

अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करें या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक है

तर्क की अवहेलना करता है कि वह तर्कहीनता की बुराई से पीड़ित है

विकृत होने का दोष, तो, निष्कर्ष को कमजोर कर दिया जाता है

कानून में। 2999

13.4 . दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (ऊपर) में, इस अदालत ने फिर से

मामला-कानून की ओर देखा और न्यायालयों की शक्ति की रूपरेखा को समझाया जो मध्यस्थता पुरस्कारों को देखते हैं। इसमें, इस न्यायालय ने न केवल उपरोक्त सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की, बल्कि गंभीर चिंता के क्षेत्र पर भी प्रकाश डालाई तथ्यात्मक पहलुओं के विच्छेदन और पुनर्मूल्यांकन के बाद न्यायिक पुरस्कारों को अलग करने में न्यायालयों की "एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति" की ओर इशारा करते हैं। इसने इस बात को दोहराते हुए कि अदालतें अपील में नहीं बैठती हैं, अभिव्यक्ति की प्रासंगिक विशेषताओं और दायरे को भी रेखांकित किया कि "अवैधता निहित है"।

मध्यस्थ पुरस्कार। इसके प्रासंगिक और महत्वपूर्ण परिच्छेद

मेंट को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

" 26. UNCITRAL मॉडल कानून और नियमों का संचयी अध्ययन,

विधायी आशय जिसके साथ 1996 का अधिनियम बनाया गया है, धारा 5

और 1996 के अधिनियम की धारा 34 यह स्पष्ट करेगी कि न्यायिक

मध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप इन आधारों तक सीमित है -

धारा 34. धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय लेते समय

अधिनियम, न्यायालयों को सख्ती से इसके अनुसार कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया है

और धारा 34 की सीमा के भीतर, प्रशंसा से बचना या तथ्य के साथ-साथ कानून के मामलों का पुनर्मूल्यांकन।

(उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम देखें। उत्तरी कोयला

फील्ड लिमिटेड. [उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम.

उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 455: (2020) 1 एससीसी (सी. आई. वी.)

570] , भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड [भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम। सरदार सरोवर नर्मदा निगम

लिमिटेड, (2022) 1 एस. सी. सी. 757 और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान

चांद राम सरन [राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद

राम सरन, (2012) 5 एससीसी 3067।)

**** एलिगंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा का राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

28. इस न्यायालय ने कई अन्य निर्णयों में धारा की व्याख्या की है।

34 मध्यस्थता पुरस्कारों की वैधता की जांच करते समय न्यायालयों द्वारा दिखाए जाने वाले प्रतिबंध पर जोर देने के लिए 1996 अधिनियम। मध्यस्थता पुरस्कारों को रद्द करने के लिए न्यायालयों के पास उपलब्ध सीमित आधार कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों के लिए अच्छी तरह से ज्ञात हैं। हालांकि, कठिनाई उत्पन्न होती है हस्तक्षेप के लिए सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने में

प्रत्येक मामले के तथ्य जो न्यायालयों के समक्ष आते हैं। अदालतों द्वारा दरकिनार करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है विच्छेदन और तथ्यात्मक पुनर्मूल्यांकन के बाद मध्यस्थता पुरस्कार

इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले मामलों के पहलू कि पुरस्कार हस्तक्षेप की आवश्यकता है और उसके बाद, पुरस्कार को रद्द करने के लिए उपलब्ध अन्य आधारों के अलावा, विकृति या पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से 1996 के अधिनियम के उद्देश्य का क्षरण होगा और इस उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास, जो मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप है। कि

इसके अलावा, इस न्यायालय के कई न्यायिक निर्णय होंगे यदि मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखा जाता है तो यह एक मृत पत्र बन जाता है

उन्हें विकृत या स्पष्ट रूप से अवैध के रूप में वर्गीकृत करना

उक्त अभिव्यक्तियों की रूपरेखा की सराहना करना।

29. पेटेंट की अवैधता अवैध होनी चाहिए जो इसकी जड़ तक जाती है बात है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई कानून की प्रत्येक त्रुटि "पेटेंट अवैधता" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। इसी तरह, कानून का गलत अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है

पेटेंट अवैधता के रूप में वर्गीकृत। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन

सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा नहीं होना "पेटेंट अवैधता" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर है। जो वर्जित है वह यह है कि अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना करें कि पुरस्कार चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से पीड़ित है

पुरस्कार, क्योंकि न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं बैठते हैं। घरेलू पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए अनुमेय आधार

धारा 34 (2-ए) के तहत पेटेंट अवैधता के आधार पर तब होता है जब मध्यस्थ एक ऐसा दृष्टिकोण लेता है जो संभव भी नहीं है, या

अनुबंध में किसी खंड की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति ऐसा न करे, या यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटककर और उन्हें आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। एक मध्यस्थता पुरस्कार में कहा गया है कि

इसके निष्कर्षों के लिए कोई कारण स्वयं को अतिसंवेदनशील नहीं बनाएगा

इस खाते पर चुनौती। मध्यस्थ के निष्कर्ष जो [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. धारा 34 (2) (बी) उन अन्य आधारों को संदर्भित करती है जिन पर एक अदालत एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द कर सकती है। यदि कोई विवाद जो मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, निर्णय का विषय है या यदि निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, तो निर्णय को रद्द किया जा सकता है। 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित स्पष्टीकरण (1) ने मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा के उद्देश्यों के लिए "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति और इसके अर्थों को स्पष्ट किया। यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ तभी टकराव में होगा जब वह धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित हो या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन हो। 1996 अधिनियम, यदि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है या यदि यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

उन तथ्यों का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अनुज्ञेय नहीं हैं। डिवीजन बेंच ने आगे कहा/डी. एम. आर. सी. बनाम। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6562] कि सी. एम. आर. एस. प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से चार साल से अधिक की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिकूल घटना के ए. एम. ई. एल. के संचालित होने के तथ्य को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया था। चूंकि मध्यस्थ एकमात्र है न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य की गुणवत्ता के साथ-साथ साक्ष्य की मात्रा के न्यायाधीश का कार्य धारा 34 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य पर न्यायाधीश होने का कार्य न्यायालय पर नहीं पड़ता है। [राजस्थान राज्य बनाम। पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (1994) 6 एस. सी. सी. 485] पक्षों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों के आधार पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचार के लिए मुद्दों को तैयार किया और जवाब दिया।

उक्त मुद्दे। बाद की घटनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

(जोर दिया गया)

एलिअंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

13.5 . हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय के लाभ ने धारा 34 के तहत हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश की ओर इशारा किया

7 अधिनियम के; और निम्नलिखित में दावे के गुण-दोष में प्रवेश करते हुए अधिनियम के 37 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया गया।

एस: -

" 8. जहाँ तक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और पुरस्कार को रद्द करने और रद्द करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में, उच्च न्यायालय ने दावे के गुण-दोष को दर्ज किया है, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अनुज्ञेय नहीं है।

9. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिर स्थिति के अनुसार

निर्णयों के आधार पर, एक पुरस्कार केवल तभी अलग किया जा सकता है जब पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो। पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34/37 के तहत अलग रखा जा सकता है, यदि पुरस्कार इसके विपरीत पाया जाता है: (क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ख) भारत का हित; या (ग) न्याय या नैतिकता; या (घ) यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है। उपरोक्त अपवादों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने दावे के गुण-दोष में प्रवेश किया है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का फैसला किया है जैसे कि उच्च न्यायालय विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील का फैसला कर रहा था।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं है। विवादित फैसला

और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं है।

13.6 . जहाँ तक अधिनियम की धाराओं के तहत हस्तक्षेप के सीमित दायरे का संबंध है, हम उपयोगी रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

-यू. एच. एल. पावर कंपनी के मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

टेड वी. हिमाचल राज्य: (2022) 4 एससीसी 116: -

" 15. यह न्यायालय भी सही के रूप में स्वीकार करता है, अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों की पुनः सराहना करने और कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या के संबंध में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लेने में एक बड़ी त्रुटि की है।

पक्षकारों को, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में ऐसा करना उक्त न्यायालय के लिए खुला नहीं था, वस्तुतः अपील न्यायालय के रूप में कार्य करना।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. जैसा कि है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र काफी संकीर्ण है, जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के दायरे की बात आती है, तो किसी आदेश की जांच करने, रद्द करने या अस्वीकार करने में अपीलीय अदालत का अधिकार क्षेत्र काफी संकीर्ण होता है।

पुरस्कार को अलग रखना, और भी अधिक सीमित होता जाता है।

और अन्य मामलों को संदर्भित किया गया और उसके बाद, इस न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों पर सिद्धांतों को लागू किया। हम उक्त निर्णय का उल्लेख करेंगे। बाद में एक उचित समय पर।

13.8 . अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक न्यायालय द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप के सीमित दायरे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो धारा 37 के तहत एक अपील में अधिक सीमित है, हम उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों के संबंध में पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच कर सकते हैं।

कार्यवाही और प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

14. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही में उसने एक विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था अधिनियम की धारा 26 के तहत लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया गया था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में देखा है और इस आधारहीन आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। हमें यह अजीब लगता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने स्वयं के रुख के विपरीत और अपने स्वयं के संशोधित अभिवचन के खिलाफ इस तरह की आपत्ति को राज्य द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती देने के आधार के रूप में पेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोवा सरकार द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर जवाबी दावे में, शुरू में यह प्रार्थना की गई थी कि दावेदार द्वारा उठाए गए सभी लेनदेन और चालानों की एक तकनीकी सह वित्तीय विशेषज्ञ के माध्यम से फिर से जांच की जानी चाहिए ताकि अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में बिलों की शुद्धता का पता लगाया जा सके, लेकिन इसके बाद, सरकार ने स्वयं अपने जवाबी दावे में संशोधन किया, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत अनुमति दी गई थी, और इस अनुरोध को हटा दिया। यह.

तब सरकार द्वारा अनुरोध किया गया कि उसने एक विशेषज्ञ की सेवाओं को नियुक्त किया है और उसकी सहायता से उस राशि पर फिर से काम किया है जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

दावेदार द्वारा देया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रार्थना को इस तरह हटाने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए इस आधार पर आगे बढ़ना उचित था कि अधिनियम की धारा 26 के तहत आवेदन को या तो निष्फल कर दिया गया था या गोवा सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था; और यह कि वह निपटान न करने के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखा पाया था।

आवेदन से। हम इस पर उच्च न्यायालय से सहमत हैं।

अंक प्राप्त करें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुरस्कार को चुनौती देते हुए, गोवा सरकार ने अपने जवाबी दावे की अस्वीकृति को उत्तेजित नहीं किया है। वास्तव में, मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से निर्णय के अनुच्छेद 31 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण

गोवा सरकार की ओर से की गई दलीलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जवाबी दावे से संबंधित विवरणों को पूरा करने के लिए अभ्यास किया गया है और सरकार को विभिन्न शीर्षों के संदर्भ में और आवश्यक राशि निर्दिष्ट करने की अनुमति दी गई है

विवरण। पुरस्कार का अनुच्छेद 31 इस प्रकार है:

" 31. मामले की सुनवाई के दौरान, 18.10.2016 पर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि उनके मुक्किल ने प्रतिदावे से संबंधित विवरण तैयार करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है, क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रतिदावे में कोई निर्दिष्ट राशि का दावा नहीं किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे चाहेंगे कि आंकड़े इस न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाएं

यदि आवश्यक हो तो अभिवचनों का संशोधन। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी को लिखित रूप में दावेदार को उस राशि से अवगत कराने की अनुमति दी जिसे प्रत्यर्थी ने विभिन्न शीर्षों के तहत तत्काल कार्यवाही में जवाबी दावे के माध्यम से और आवश्यक विवरणों के साथ दावा किया था। दावेदार को अपनी आपत्तियाँ दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

14.1 . सरकार की ओर से एक अन्य निवेदन यह रहा है कि दावेदार द्वारा कुछ दस्तावेजों को पेश नहीं करने के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उनके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था। यह फिर से साक्ष्य का एक नियम है कि प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है या नहीं; और किस प्रभाव के लिए। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया है और कहा है कि अधिकांश दस्तावेज गोवा सरकार को उपलब्ध कराए गए थे। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि गोवा सरकार द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराए गए थे क्योंकि दावेदार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे दस्तावेज संबंधित समय पर उसके पास उपलब्ध नहीं थे या संबंधित समय पर मौजूद नहीं थे। यह भी माना गया है कि गोवा सरकार द्वारा कोई गंभीर पूर्वाग्रह स्थापित करने की अनुपस्थिति में, [2023] 8 एस. सी. आर. के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राकृतिक न्याय केवल इसलिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने वाले आवेदन पर औपचारिक आदेश देने में विफल रहा था। हम उच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों से सहमत हैं।

14.2 . गोवा सरकार की इस दलील कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अतिरिक्त लिखित प्रस्तुति दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया था, पर भी उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ विचार किया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया था क्योंकि विद्वान मध्यस्थ के समक्ष कम से कम दो बैठकें/सुनवाई हुई थीं।

गोवा सरकार ने दावेदार के लिखित स्पष्टीकरण/प्रस्तुतियों के जवाब में न तो लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं और न ही अनुमति मांगी। हम भी इन निष्कर्षों से सहमत हैं।

14.3 . वास्तव में, उपरोक्त प्रकृति की प्रस्तुतियाँ, प्रयास

इस तरह के अति-तकनीकी लेकिन आधारहीन आधारों पर मध्यस्थता की कार्यवाही में दोष ढूँढना केवल राज्य की ओर से किसी भी तरह से निर्णय पर सवाल उठाने और हस्तक्षेप की मांग करने के प्रयास को दर्शाता है, चाहे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत कुछ भी हों।

14.4 . मामले के उपरोक्त प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के रिकॉर्ड पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है

और इन तर्कों को अस्वीकार करने के लिए केवल अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर आगे बढ़ा है।

15. हालाँकि, सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय अन्य बिंदुओं पर विचार करते समय उन सीमाओं के भीतर रहा।

दावे की वस्तुओं से संबंधित चुनौती और उस संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विचार। हम लागू सिद्धांतों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के बिंदु-वार विचार की जांच कर सकते हैं।

वैकल्पिक के उपयोग पर परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित पुरस्कार

ईंधन

16. दावेदार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया है

जिसे इसने रुपये के परिवर्तनीय शुल्क के लिए अलग रखा है। 24.66 एक करोड़। दावेदार का मामला यह है कि जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने निर्णय को दरकिनार किया है, वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था; कि किसी भी मामले में, राज्य ने पी. पी. ए. के ऐसे खंडों का उल्लेख किया है जो वैकल्पिक ईंधन के रूप में आर. एल. एन. जी. का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति पर लागू नहीं थे; और ये खंड केवल आपूर्ति के लिए लागू थे।

ईंधन के रूप में 'नाफ्था' का उपयोग करके बिजली। इसके विपरीत, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने संपूर्ण रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से संपर्क किया है।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पूरी तरह से गलत कोण से मामला; और जब न्यायाधिकरण ने गलत प्रश्न, परिणाम गलत उत्तरों का रहा है। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण की ओर से एक घोर अवैधता और विकृति रही है।

16.1 . हमें विद्वान महान्यायवादी के निवेदन को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। हमारे विचार में, ईंधन की घटती कीमत और डॉलर की दर के आधार पर चालान जुटाने के अधिकार के मुद्दे पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य की पूरी तरह से जांच करने और अपने समक्ष उठाए गए मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बाद दावेदार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

16.2 . प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद और पूरे दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित शब्दों में तथ्यों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया: -

" 41. ऊपर देखे गए तथ्य जो पूरी तरह से इस पर आधारित हैं -

न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए दस्तावेजी रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि दावेदार द्वारा 21 मार्च 2013 के अपने पत्र के तहत किया गया प्रस्ताव उपरोक्त संचार में निहित सूत्र के आधार पर दर पर ऊर्जा की आपूर्ति का प्रस्ताव था। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मासिक शुल्क में परिवर्तनीय शुल्क की गणना में परिवर्तन को छोड़कर संपूर्ण पी. पी. ए. और अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। लागतों को निर्धारित करने के लिए सूत्र को "प्रस्तावित मासिक परिवर्तनीय" के रूप में भी वर्णित किया गया था।

शुल्क सूत्र "एक मासिक नमूना गणना के आधार पर

तेल की भूमि लागत और डॉलर दर के अनुमानित मूल्यों को जोड़ा गया था

यह दिखाने के प्रस्ताव के लिए कि लागत उत्तरदाता द्वारा भुगतान की जा रही लागत से कम होगी। जब प्रत्यर्थी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 26 अप्रैल 2012 के अपने पत्र द्वारा जवाब दिया, जिसमें रुपये की दर से लागत का उल्लेख किया गया था। 8.58 प्रति इकाई, जिसे "संशोधित निश्चित दर" के रूप में वर्णित किया गया था, दावेदार ने 30 अप्रैल 2013 के अपने पत्र में प्रतिवादी को यह बताते हुए तुरंत स्थिति स्पष्ट कर दी कि 21 मार्च 2013 के प्रस्ताव में उल्लिखित कीमत बिजली की एक निश्चित लागत के लिए नहीं थी।
आपूर्ति की गई, और यह कि वही बाजार में ईंधन की कीमत और विनिमय दर के आधार पर भिन्न होगा। इसलिए उन्होंने प्रत्यर्थी से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया कि शुल्क एक सूत्र था

यह बाजार में ईंधन की कीमत में बदलाव और डॉलर में बदलाव के आधार पर अलग-अलग होगा। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पक्ष थे

सामने आए मतभेदों को हल करने में सक्षम नहीं, और अंततः [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मामला 22 मई, 2013 को गोवा सरकार के मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। इस मामले पर विचार करने के बाद, मंत्रिमंडल ने दावेदार से दावेदार के प्रस्ताव में दी गई दर पर बिजली खरीदने का बहुत स्पष्ट और स्पष्ट निर्णय लिया, जो गैस और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर अलग-अलग होगा।

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव। अनुपालन की रिपोर्ट करने के अनुरोध के साथ सभी संबंधित कार्यालयों को निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। अगले ही दिन, प्रत्यर्थी ने 23 मई को अपने पत्र द्वारा

2013 इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने 21 मार्च 2013 के अपने पत्र में दावेदार द्वारा प्रस्तावित सूत्र के अनुसार बिजली की खरीद जारी रखने का फैसला किया था।

मौजूदा पी. पी. ए. की समाप्ति तक ईंधन और डॉलर की दरें। उसी संचार ने यह भी निर्देश दिया कि बिजली के बिल होने चाहिए

ईंधन और डॉलर की कीमतों के उचित प्रलेखन के साथ प्रस्तुत किया गया।

42. ये तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि दावेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की कीमत निश्चित डॉलर दर या ईंधन की लैंडिंग लागत पर आधारित नहीं थी। प्रस्ताव ने स्पष्ट रूप से इन शुल्कों को परिवर्तनशील बना दिया, और स्थिति को और स्पष्ट कर दिया जब प्रतिवादी ने इसे एक निश्चित दर सूत्र के रूप में गलत तरीके से समझा। अंततः गोवा सरकार के मंत्रिमंडल ने दावेदार के पक्ष में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया। यह तर्क दिया गया कि मंत्रिमंडल का निर्णय बाध्यकारी नहीं था क्योंकि इसके अनुसार कोई आदेश नहीं था राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था। बछेतर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 395) के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जब तक मंत्रिमंडल के फैसले का पालन राज्य द्वारा तैयार किए गए औपचारिक आदेश द्वारा नहीं किया जाता है।

सरकार, इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से असमर्थनीय है। तथ्यों पर, न्यायालय को भेजे गए निर्णय में फाइल में राजस्व मंत्री के नोट से संबंधित था, और यह मंत्रिमंडल द्वारा अपनी बैठक में लिया गया निर्णय नहीं था। दूसरा, तत्काल मामले में मंत्रिमंडल के निर्णय से सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था कि वे आदेश के अनुसार कार्य करें और अनुपालन की रिपोर्ट दें। उक्त निर्णय के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दावेदार को एक पत्र लिखा गया था जिसमें परिवर्तनीय शुल्क के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।

ईंधन और डॉलर की प्रचलित लागत के अनुसार। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार ने मंत्रिमंडल के उक्त निर्णय पर कार्रवाई की।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

43. इन सभी कारणों से, न्यायाधिकरण ने पाया कि

दावेदार कि प्रत्यर्थी शक्ति के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य था

उसके द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार खरीदा गया

दावेदार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए चालान का आधार

तेल और डॉलर की परिवर्तनीय लागत को ध्यान में रखते हुए, स्वीकार किया जाना चाहिए, और इसके विपरीत प्रत्यर्थी की याचिका को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

16.3 . जहाँ तक गैर के संबंध में राज्य का विवाद है

खंड 12 का विचार। 4 12. 1 तक। 7 पी. पी. ए. के संबंध में, हमारे विचार में, दावेदार का यह कहना सही है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया मुख्य मुद्दा केवल यह था कि क्या समझौता था ईंधन मूल्य की एक निश्चित दर और अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये के संदर्भ में विनिमय की एक निश्चित दर पर बिजली की आपूर्ति करना।

16.4 . ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अभिवचनों के अंतिम भाग में,

गोवा सरकार ने उपरोक्त खंड 12.1 का उल्लेख किया है। 4 12. 1 तक। 7 लेकिन, मामले का तथ्य यह है कि उन्हें पक्षों द्वारा कानून या तथ्यों के भौतिक प्रस्ताव बनाने के रूप में नहीं माना गया था ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दे का हिस्सा बन सके। यहां तक कि मुद्दों के निपटारे से संबंधित पहले सिद्धांतों पर भी, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIV नियम 1 में, न्यायालय, नियमित दीवानी मुकदमे पर विचार करते समय, यह पता लगाएगा कि तथ्य या कानून के किस भौतिक प्रस्ताव पर पक्षकार भिन्न हैं, और फिर उन मुद्दों को तैयार करेगा और दर्ज करेगा जिन पर मामले का सही निर्णय निर्भर प्रतीत होता है। वर्तमान मामला मध्यस्थता का था।

18 आदेश XIV नियम 1 सी. पी. सी. निम्नानुसार है: - “ 1. मुद्दों को तैयार करना। — (1) समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब तथ्य या तथ्य का एक भौतिक प्रस्ताव

कानून की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और दूसरे द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(2) भौतिक प्रस्ताव कानून या तथ्य के वे प्रस्ताव हैं जो एक वादी को मुकदमा करने का अधिकार दिखाने के लिए आरोप लगाना चाहिए या प्रतिवादी को अपने बचाव का गठन करने के लिए आरोप लगाना चाहिए।

(3) प्रत्येक सामग्री प्रस्ताव की एक पक्ष द्वारा पुष्टि की गई और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया

एक विशिष्ट मुद्दे का विषय बनेगा।

((क) तथ्य के मुद्दे,

((ख) कानून के मुद्दे।

(5) वाद की पहली सुनवाई में न्यायालय, वाद और लिखित कथन, यदि कोई हो, को पढ़ने के बाद और आदेश X के नियम 2 के तहत जांच के बाद और पक्षों या उनके अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, यह पता लगाएगा कि तथ्य या कानून के किन भौतिक प्रस्तावों पर पक्षकार भिन्न हैं, और उसके बाद उन मुद्दों को तैयार करने और दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेगा जिन पर मामले का सही निर्णय निर्भर प्रतीत होता है। (6) इस नियम में कुछ भी न्यायालय से उन मुद्दों को तैयार करने और दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जहां

मुकदमे की पहली सुनवाई में प्रतिवादी कोई बचाव नहीं करता है। "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और, जाहिर है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रत्येक अनुरोध या विवादित तथ्य पर मुद्दों को तैयार करने के लिए बाध्य नहीं था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण से केवल उसके समक्ष प्रस्तुत विवाद पर मध्यस्थता करने की अपेक्षा की गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, वर्तमान मामले में, पक्षों ने स्वयं उन मुद्दों को संक्षिप्त रूप से तैयार किया जिन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देने की आवश्यकता थी और उसमें, परिवर्तनीय शुल्कों के इस मामले के संबंध में, पूछा गया प्रश्न गोवा सरकार के इस दावे के संदर्भ में था कि दावेदार जून, 2013 से आर. एल. एन. जी. को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए बिजली की आपूर्ति के लिए ईंधन की कीमत की निश्चित दर और अमेरिकी डॉलर से आई. एन. आर. की कीमत के संदर्भ में विनिमय की एक निश्चित दर के आधार पर बिजली की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ था।

34 पुरस्कार का-यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया। इसलिए न्यायाधिकरण ने सही संकेत दिया कि वास्तविक मुद्दा यह था कि क्या दावेदार द्वारा तैयार किए गए चालान दावेदार द्वारा किए गए प्रस्ताव के नियमों और शर्तों के अनुसार थे और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए थे; और विवाद का मूल यह था कि क्या आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की कीमत वास्तविक उतार-चढ़ाव के बावजूद एक निश्चित डॉलर दर और एक निश्चित आयात मूल्य पर आधारित थी। न्यायाधिकरण ने वास्तव में उस संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों को स्वीकार किया और दावेदार के पक्ष में इस मुद्दे को निर्धारित किया।

16.5 . वास्तविक मुद्दे के सामने पेश किए गए और उत्तेजित होने को देखते हुए

स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। यह प्रस्तुतियों के साथ जोड़ा जाता है दावेदार ने कहा कि पी. पी. ए. में "ईंधन आपूर्ति अनुबंध" की परिभाषा दावेदार और एक ईंधन आपूर्तिकर्ता के बीच "नाफ्था" की आपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध तक सीमित थी, और वैकल्पिक ईंधन से भी संबंधित नहीं थी। तैयार संदर्भ के लिए, हम पी. पी. ए. में "ईंधन" की परिभाषाओं के साथ-साथ "ईंधन आपूर्ति अनुबंध" को भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो निम्नानुसार है: -

" " 'ईंधन' का अर्थ है नाफ्था या कोई वैकल्पिक ईंधन;

' ईंधन आपूर्ति अनुबंध का अर्थ होगा कोई भी अनुबंध जिसमें प्रवेश किया गया हो।

नाफ्था की आपूर्ति के लिए आर. एस. पी. सी. एल. और किसी भी ईंधन आपूर्तिकर्ता के बीच

खंड 12 के अनुसार; "

16.5. 1 . यदि "वैकल्पिक ईंधन" को भी "नाफ्था" के साथ पढ़ा जाना है।

उपरोक्त परिभाषा में, वह या तो अनुबंध को फिर से लिखना होगा या

कम से कम दस्तावेज़ के निर्माण के सिद्धांतों का विस्तार करके अनुबंध में कुछ पड़ना। यह, हमारे विचार में, अनुबंध की शर्तों के ऐसे निर्माण के क्षेत्र में यात्रा करेगा जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नहीं थे।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पक्षकारों द्वारा वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए सहमत होने के बाद ईंधन की दर और विदेशी मुद्रा की निश्चित दर।

16.6 . हमने केवल पक्षों के बीच लेन-देन की मुख्य विशेषताओं का व्यापक रूप से उल्लेख किया है। वास्तव में, अभिलेख के अधिक विस्तार और विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने वास्तव में आवश्यक विवरणों में मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच की है।

16.7 . किसी भी मामले में, सभी दस्तावेज जो उस लागत को दर्शाते हैं जिस पर वैकल्पिक ईंधन की खरीद की गई थी और प्रचलित डॉलर दर का समर्थन किया गया था

प्रत्येक चालान के साथ गोवा सरकार को भेजे गए मूल्य प्रमाणपत्रों द्वारा, और ऐसे प्रमाण पत्र सार्वजनिक क्षेत्र से थे

उपक्रम। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और न ही गोवा सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि उसने या तो समकालीन रूप से कोई दस्तावेज माँगा था या ऐसे प्रमाणपत्रों की शुद्धता पर विवाद किया था या इनकार किया था।

16.8 . मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने देखा है कि मंत्रिमंडल का निर्णय गोवा सरकार द्वारा ही उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वहाँ है।

यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विचार के बजाय उच्च न्यायालय के विचार के खिलाफ काम करता है।
17.1 . जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अनुबंध के सभी उक्त खंडों को "ईंधन आपूर्ति" और फिर, [2023] 8 एस. सी. आर. शीर्षक के तहत पुनः प्रस्तुत किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके संचालन से संबंधित विशेषताओं, विशेष रूप से खंड 12.1 पर विस्तार से चर्चा की। 4 12. 1 तक। 7 . उच्च न्यायालय ने इस पहलू को एक महत्वपूर्ण मुद्दा पाया है और इस पर विचार न करना एक अवैध अधिकार माना गया है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया गया:

परिवर्तनीय प्रभारों की ओर, जिनमें से ईंधन घटक था सबसे प्रभावशाली। अंततः, विद्वान मध्यस्थ ने रुपये की राशि में एक पुरस्कार दिया है। 24.66 नाफ्था से ईंधन के स्विच के बाद परिवर्तनीय शुल्क के लिए करोड़ (लगभग)

आरएलएनजी। इस तरह का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार संविदात्मक खंड 12.1 के साथ प्रयोज्यता और गैर-अनुपालन के बारे में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बहुत कम विचार या मूल्यांकन किए बिना किया गया है। 4 12. 1 तक। 7 . यह पेटेंट अवैधता के बराबर है क्योंकि उस हद तक पुरस्कार को खंड 12.1 में पाए जाने वाले संविदात्मक प्रावधानों की अनदेखी या यहां तक कि अवहेलना भी कहा जा सकता है। 4 12. 1 तक। 7 पी. पी. ए. से। इस हद तक पुरस्कार को पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित माना जाएगा।

क्योंकि पुरस्कार खंडों में संविदात्मक प्रावधानों के लागू होने और गैर-अनुपालन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है।

12.1. 4 12. 1 तक। 7 . "

17.2 . उच्च न्यायालय ने यह भी कहा और दोहराया कि हस्तक्षेप न्यायालय के असहमत होने के कारण नहीं किया जा रहा था

मध्यस्थ द्वारा संविदात्मक खंडों की किसी भी व्याख्या के साथ लेकिन क्योंकि मध्यस्थ प्रासंगिक संविदात्मक पर गौर करने में विफल रहा प्रावधान। उच्च न्यायालय ने अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए कहा कि

इसके अंतर्गत: -

" 98. हमारे अनुसार, ये सभी भविष्यवाणियाँ तब आकर्षित होती हैं जब परिवर्तनीय शुल्कों से संबंधित विवादित पुरस्कार की बात आती है। हस्तक्षेप किसी भी तरह से योग्यता-आधारित नहीं है। हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि वर्तमान मामले में मध्यस्थ विज्ञापन देने में भी विफल रहा है

संविदात्मक प्रावधानों की प्रयोज्यता और गैर-अनुपालन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दों में से एक के गुण-दोष पर बहुत कम ध्यान दें। हस्तक्षेप इसलिए नहीं है क्योंकि विद्वान मध्यस्थ द्वारा संविदात्मक खंडों की व्याख्या गलत है या क्योंकि हम ऐसी व्याख्या से असहमत हैं।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि विद्वान मध्यस्थ देखने में भी विफल रहा

संविदात्मक प्रावधानों में यह पता लगाने के लिए कि क्या उन्हें दिया गया था नाफ्था से आर. एल. एन. जी. में ईंधन के स्थानांतरण के बाद। द.

हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि विद्वान मध्यस्थ ध्यान देने में विफल रहा

संविदात्मक खंडों की व्याख्या और यह पता लगाने के लिए कि क्या वे उल्लंघन किया गया जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया था, हालांकि द्वारा इनकार किया गया था

उत्तरदाता। बहुत कम लेने के लिए भी विज्ञापन किए बिना

संविदात्मक प्रावधानों पर विचार करें जो

पक्षों के बीच संबंध, विद्वान मध्यस्थ नहीं था

रुपये का पुरस्कार देने में न्यायसंगत। 24.66 के पक्ष में करोड़

उत्तरदाता। तदनुसार, हम विवादित पुरस्कार को अलग रखते हैं

जिस हद तक यह रु। 24.66 प्रत्यर्थी के लिए करोड़

परिवर्तनीय प्रभार "।

18. जैसा कि देखा गया है, मध्यस्थता आदेश एक सामान्य न्यायिक आदेश नहीं है।

ताकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत न्यायालयों द्वारा हल्के से हस्तक्षेप किया जा सके जैसे कि किसी के खिलाफ अपील या संशोधन से निपटना। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय। अभिव्यक्ति "पेटेंट अवैधता" है

इस न्यायालय द्वारा पहले निर्दिष्ट मामलों में उजागर किया गया था। दोहराए जाने वाला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल एक अवैधता नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, बल्कि इसे "एक पेटेंट अवैधता" होना चाहिए।

जो

स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह निर्णय के सामने स्पष्ट होना चाहिए, न कि उस पर जिसे दलीलों और साक्ष्य के लंबे विश्लेषण के माध्यम से निकाला जाता है। बेशक, जब पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो मामला अलग होगा और इस तरह की कमी वाला निर्णय सीधे अधिनियम की धारा 28 (3) द्वारा प्रभावित होगा, जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लेनदेन पर लागू व्यापार के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने का आदेश देता है। जैसा कि इस न्यायालय ने एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में कहा है, यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो निर्माण से प्राप्त कटौती के संदर्भ में पुरस्कार को अलग नहीं किया जा सकता है। हस्तक्षेप की संभावना तभी उत्पन्न होगी जब मध्यस्थ का निर्माण किया जाए

ऐसा जो किसी भी निष्पक्ष और विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था।

19. एस. ए. एल. उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला

विद्वान महान्यायवादी एक उपयुक्त उदाहरण है कि "पेटेंट अवैधता" को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत कब अमल में आते हैं। उस मामले में, साल के बीजों की आपूर्ति से संबंधित अनुबंध में, प्रतिवादी-ठेकेदार ने 21.12.1998 तक काम करना जारी रखा था, जब अनुबंध समाप्त कर दिया गया था [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून में परिवर्तन के अनुसार। इसके बाद प्रत्यर्थी ने कथित रूप से भुगतान की गई लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि वापस करने का दावा किया।

राज्य के लिए अतिरिक्त। विवाद अंततः मध्यस्थता का कारण बना और प्रतिवादी के पक्ष में एक मध्यस्थ निर्णय दिया गया जिसमें अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

19.1 . इसमें, अपीलकर्ता राज्य द्वारा चुनौती का विशिष्ट आधार यह था कि मध्यस्थ ने अनुबंध की बाध्यकारी अवधि की अनदेखी की थी

"पर्यवेक्षण शुल्क" की वसूली से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करना। इस तरह की बाध्यकारी अवधि को मध्यस्थ द्वारा यह देखते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि इस तरह के किसी भी "अप्रत्यक्ष खर्च" को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इस न्यायालय ने पाया कि पर्यवेक्षण शुल्क राज्य द्वारा लगाया गया था और पक्षकारों द्वारा समझौते में प्रवेश करने की तारीख से प्रतिवादी द्वारा बिना किसी अधिकार के भुगतान किया गया था और अनुबंध की समाप्ति के बाद ही

प्रतिवादी ने पर्यवेक्षण शुल्क के प्रति विवाद उठाया। यह मध्यस्थ का अनुबंध की शर्तों को नजरअंदाज करने और ओवरराइड करने का एक उत्कृष्ट मामला था, जैसा कि इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से प्रतीत होता है।

मामले के तथ्यों के संदर्भ में:

" 23. मामले के तथ्यों के संदर्भ में, यह निर्विवाद है कि हालांकि अपीलकर्ता राज्य ने प्रतिवादी कंपनी के दावे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति जताई थी

पर्यवेक्षण शुल्क की कटौती, जिसके लिए वह खंड पर निर्भर था

6 (बी) समझौते के और 27-7-1987 दिनांकित परिपत्र में यह दावा करने के लिए कि खर्चों के साथ पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली प्रतिवादी कंपनी के साथ निष्पादित अनुबंध का एक हिस्सा और पार्सल था, उक्त आपत्ति को विद्वान एकल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए और यह देखते हुए कि

खर्च में साल के बीजों की लागत के लिए गणना की गई राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाने का प्रावधान है।

खर्च किया गया, भी नजरअंदाज कर दिया गया। विशेष रूप से, प्रत्यर्थी कंपनी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क लगाया जा रहा था और उसके द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए अग्रिम भुगतान के एक हिस्से के रूप में बिना किसी अवज्ञा के भुगतान किया जा रहा था, ठीक उस तारीख से जब पक्षों ने पहला समझौता किया था अर्थात् 30-8-1979 से। यह तथ्य नमूने की प्रतियों से भी सामने आता है।

अपीलकर्ता राज्य द्वारा दायर आदेशों की अपील के साथ कि एलिऐंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करें कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले साल के बीजों की लागत में "पर्यवेक्षण शुल्क" शामिल था जिसे स्थानीय भाषा में "पर्यवेक्षण व्याय" के रूप में वर्णित किया गया था। अपीलकर्ता राज्य द्वारा आईडी1 पर दूसरे अनुबंध को समाप्त करने के बाद ही प्रतिवादी कंपनी ने विवाद उठाया और पहली बार साल के बीजों की आपूर्ति के लिए किए गए पर्यवेक्षण शुल्क के लिए अपीलकर्ता राज्य को कथित रूप से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया। हमारी राय में, यह पेटेंट अवैधता है जो मध्यस्थता पुरस्कार के सामने प्रकट होती है

चूंकि पार्टियों को नियंत्रित करने वाले समझौते के स्पष्ट नियम और शर्तें और साथ ही जारी किया गया परिपत्र दिनांक 27-7-1987 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

19.2 . अभिलेख के सामने इस तरह की स्पष्ट त्रुटि को देखते हुए, न्यायालय ने मामले को पेटेंट अवैधता का पाया जो मामले और विवादित पुरस्कार को हटाने वाला था, जहां तक अनुमति है

प्रत्यर्थी से वसूल किए गए पर्यवेक्षण शुल्क को निरस्त कर दिया गया और अधिनियम की शर्तों और प्रासंगिक परिपत्र के साथ सीधे टकराव में होने के कारण अलग कर दिया गया। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

पक्षों को नियंत्रित करने वाला अनुबंध निश्चित रूप से "पेटेंट अवैध आधार" को आकर्षित करेगा, क्योंकि उक्त निरीक्षण सकल राशि के बराबर है। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय देते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देता है। उक्त "पेटेंट अवैधता" न केवल पुरस्कार के चेहरे पर स्पष्ट है, यह मामले की जड़ तक जाती है और हस्तक्षेप के योग्य है। तदनुसार, वर्तमान अपील

अपीलार्थी राज्य द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी से वसूल किए गए "पर्यवेक्षण शुल्क" की कटौती की अनुमति साल [2023] 8 एस. सी. आर. की कीमत की गणना करते समय इसके द्वारा किया गया व्यय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों और प्रासंगिक परिपत्र के साथ सीधे संघर्ष में होने के कारण बीज को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। दिनांकित आक्षेपित निर्णय 21-10-2009 को संशोधित किया गया है उपरोक्त सीमा "।

20. इस मामले की जांच एक और कोण से की जा सकती है। यदि संचार के आदान-प्रदान के साथ पक्षों द्वारा सहमत शर्तें आई. डी. 1 से शुरू करके इसे नजरअंदाज किया जाना था, इसका परिणाम उन पक्षों के अनुबंध की ऐसी शर्तों की अनदेखी करना होगा जो अस्तित्व में आई थीं और जो दोनों के लिए बाध्यकारी थीं। इस प्रकार, इस तथ्य के साथ कि केवल सीमित विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया था (यानी कि क्या बिजली की आपूर्ति ईंधन की निश्चित दर और मुद्रा की निश्चित दर के आधार पर या परिवर्तनीय शुल्कों के आधार पर की जानी थी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण, हमारे विचार में, गुमराह होने और इस तरह के विश्लेषण में प्रवेश करने के बजाय, उठाए गए मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में उचित रहा है जो नहीं था।

हाथ में मुद्दे पर टिप्पणी करें।

21. उपरोक्त कारणों से, हमारे विचार में, चुनौती के लिए कोई आधार नहीं है

अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित पुरस्कार के संबंध में बनाया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय खंड 12.1 पर तथाकथित विचार न करने के आधार पर परिवर्तनीय आरोपों से संबंधित अधिनिर्णय को रद्द करने में सही नहीं रहा है। 4 12. 1 तक। 7 पी. पी. ए. 21.1 . दूसरे शब्दों में कहें तो, उच्च न्यायालय ने अधिकारिता की सीमा की याद दिलाते हुए भी, खंड 12.1 मानते हुए साक्ष्य को व्यापक रूप से विच्छेदित करके वही त्रुटि की है। 4 12. 1 तक। 7 वे उन सामग्री प्रस्तावों पर बारीकी से विचार किए बिना मामले के निर्णायक थे जो विवाद का गठन करते थे और जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जहां तक परिवर्तनीय शुल्कों का संबंध है, न्यायाधिकरण के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या दावेदार वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा की निश्चित दर के साथ निश्चित शुल्क पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था। इस प्रश्न का निर्धारण अनिवार्य रूप से नए अनुबंध के संदर्भ में किया जाना था जो कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है।

बी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पक्षों के बीच संचार के आदान-प्रदान के साथ अस्तित्व में आया। मध्यस्थ ने उस साक्ष्य के संदर्भ में और उसके विश्लेषण के बाद मामले का सटीक निर्णय लिया। यह न तो मध्यस्थ का मामला था कि उसने इस मुद्दे पर लागू अनुबंध की शर्तों को ध्यान में नहीं रखा था और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष था जिसे कोई भी निष्पक्ष या तर्कसंगत व्यक्ति संभवतः कभी प्रस्तुत नहीं कर सकता था। पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए गए मुख्य विवाद के आलोक में, विद्वान महान्यायवादी की प्रस्तुतियों को देखते हुए, कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न की जांच नहीं की है कि क्या विचाराधीन पत्राचार के परिणामस्वरूप अनुबंध के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ है, हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाते हैं क्योंकि ईंधन के संबंध में अनुबंध की शर्तों का नवीनीकरण बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं था। मूल सवाल यह था कि नई शर्तें कैसे काम करेंगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कानून के अनुसार ठीक उसी पर विचार किया है।

22. यहाँ ऊपर क्या देखा गया है और अस्वीकृति में रखा गया है

परिवर्तनीय प्रभावों से संबंधित अधिनिर्णय की मद में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप कमोवेश अन्य मदों पर भी लागू होता है, जहां उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और अधिनिर्णय को पलट दिया है। पूर्वगामी विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें अन्य सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर संक्षिप्त रूप से विचार करना ही पर्याप्त होगा क्योंकि हम पाते हैं कि इस तरह के प्रत्येक मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश किया है।

मानो एक नियमित अपील से निपट रहा हो। यह उच्च न्यायालय का एक स्पष्ट मामला रहा है जो धारा 34 की परिधि से परे यात्रा कर रहा है और साथ ही इसकी धारा 37 भी।

1996 का अधिनियम।

संयंत्र के अवमूल्यन से संबंधित पुरस्कार

23. जहां तक डाउनरेटिंग का संबंध है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा

यह था कि क्या संयंत्र को पी. पी. ए. की समाप्ति तक कम करने की आवश्यकता थी जैसा कि गोवा सरकार ने बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था।

23.1 . मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पक्षों की संविदात्मक शर्तों पर विचार किया और ऐसे नियमों और शर्तों की व्याख्या पर एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि पक्षों के बीच निष्पादित विभिन्न पूरक पीपीए से पता चलता है कि संयंत्र की निर्धारित क्षमता घटकर 19.8 मेगावाट हो गई थी और दावेदार का दायित्व ऐसी क्षमता के क्षरण के किसी भी संदर्भ के बिना 19.8 मेगावाट तक की आपूर्ति का आश्वासन देने तक सीमित था। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि गोवा सरकार का यह तर्क देना उचित नहीं था कि कोई [2023] 8 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेटेड क्षमता का वार्षिक मूल्यांकन। इस मुद्दे के संबंध में, यह अधिक स्पष्ट है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के प्रावधानों पर विचार किया था और उस पर एक विशेष दृष्टिकोण लिया था। न्यायाधिकरण

अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार:

" 48. से संबंधित बहस के स्तर पर एक मुद्दा उठाया गया था

संयंत्र की उत्पादन क्षमता को सालाना कम करना

के वाणिज्यिक संचालन के बाद पहले वर्ष से शुरू पौधा। इस तरह की याचिका में नहीं उठाया गया प्रतीत होता है

प्रत्यर्थी द्वारा रक्षा का वक्तव्य भले ही यह है

मूल उपकरण निर्माता (ओ. ई. एम.) की उत्पादन क्षमता को कम करने की अनुशंसाओं से संबंधित दस्तावेज "अनुबंधित क्षमता" की परिभाषा में परिकल्पित, जिसकी सिफारिशों के अनुसार उत्पादन क्षमता की डाउन रेटिंग के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए आवश्यक था

मूल उपकरण निर्माता।

49. पी. पी. ए. के संदर्भ में प्रतिवादी के अनुसार,

वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष में अनुबंधित क्षमता को 39.402 KW के रूप में परिभाषित किया गया था और लगातार वर्षों में मूल उपकरण निर्माता की सिफारिश के अनुसार वार्षिक रूप से कम मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, दावेदार ने प्रत्यर्थी को प्रस्तुत किए गए किसी भी बिल में डाउन रेटिंग कारक को ध्यान में नहीं रखा। विवाद उत्पन्न होने के बाद, प्रत्यर्थी ने कहा कि डाउन रेटिंग कारक वर्ष 2000 से लागू किया जाना चाहिए था, जो वाणिज्यिक संचालन का दूसरा वर्ष था।

ओ. ई. एम. सिफारिशों की शर्तें। इसलिए यह था कि

प्रत्यर्थी ने दावेदार से आवश्यक दस्तावेज मांगे

ओ. ई. एम. की सिफारिशों के संबंध में, लेकिन उन्हें प्रदान नहीं किया गया था, यह तर्क देते हुए कि उक्त दस्तावेज दावेदार के पास उपलब्ध नहीं थे। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता को डाउन रेटिंग कारक की गणना करने के लिए अन्य सामग्री का उपयोग करना पड़ा। प्रत्यर्थी ने द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना पर भरोसा किया है सरकार डाउन रेटिंग की गणना करेगी। उक्त अधिसूचना में कहा गया है कि डाउन रेटिंग संचालन के दूसरे वर्ष से शुरू होगी और पांचवें वर्ष तक जारी रहेगी, जिसके बाद एलिएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

संयंत्र की मरम्मत करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप छठे वर्ष में,

डाउन रेटिंग नगण्य होगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के आधार पर, प्रतिवादी ने वर्ष 2000 से डाउन रेटिंग को ध्यान में रखते हुए गणना की है।

50. दावेदार ने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि बिजली मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उसे राजपत्र में विधिवत अधिसूचित नहीं किया जाता है। प्रत्यर्थी ने विधिवत अधिसूचित किसी भी अंतिम अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया है। हो सकता है कि सरकार ने अच्छे कारणों से अधिसूचना जारी नहीं करने के बारे में सोचा हो। केवल एक मसौदा अधिसूचना होने के कारण जो अंततः कभी जारी नहीं की गई थी, इसका कानून में कोई मूल्य नहीं है और प्रतिवादी इस तरह की मसौदा अधिसूचना से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

बाद के वर्षों में सिफारिश। बाद में दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की उत्पादन केंद्र को ओपन साइकिल से 48 मेगावाट क्षमता के संयुक्त चक्र उत्पादन केंद्र में बदलना। 10 सितंबर 1997 को एक पूरक पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था जिसमें दावेदार को गोवा में उपभोक्ताओं को सीधे 39.8 मेगावाट से अधिक बिजली बेचने की अनुमति दी गई थी। दावेदार द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद

इसके बाद एक वर्ष पूरा होने पर, 14 अगस्त 1999 को विद्युत केंद्र के साथ दूसरा पूरक समझौता 20 सितंबर 2000 को किया गया, जिसके तहत प्रत्यर्थी ने विद्युत केंद्र पर उत्पन्न 2000 किलोवाट की सीमा तक पूरी या आंशिक रूप से बिजली सीधे गोवा के किसी भी उपभोक्ता को बेचने के लिए सहमति व्यक्त की। ऐसे अन्य पूरक समझौतों का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुबंधित क्षमता की पूर्व परिभाषा

अनुमति दी गई और पूरी तरह से बदल दिया गया। डाउन रेटिंग के संबंध में मुद्दा इस प्रकार अप्रासंगिक हो गया, और किसी भी घटना में बाद के लिखित समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, पहले के समझौते में संशोधन करते हुए, आगे किसी डाउन रेटिंग का कोई सवाल ही नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया था। पक्ष संविदात्मक प्रावधानों से बाध्य हैं। पक्षों के बीच निष्पादित विभिन्न पूरक पी. पी. ए. स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि रेटेड क्षमता को बाद में घटाकर 19.8 मेगावाट कर दिया गया था और दावेदार का दायित्व [2023] 8 एस. सी. आर. का आश्वासन देने तक सीमित था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षरण के संदर्भ के बिना 19.8 मेगावाट तक की आपूर्ति

ऐसी क्षमता। इसलिए प्रतिवादी में उचित नहीं है

यह तर्क देते हुए कि रेटेड क्षमता की सालाना कथित डाउन रेटिंग थी।
न्यायाधिकरण ने तब वृत्तचित्र पर विचार किया

23.2 . मध्यस्थ

इसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांकित ओ. ई. एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी शामिल है।

. 2005 और दिनांक 05.04.2007 की बैठक के कार्यवृत्त, जहां मुद्दे का निपटारा किया गया और उस तारीख तक के सभी बिलों का मिलान किया गया और भविष्य के बिलों को इस आधार पर उठाया गया कि कोई डाउनरेटिंग नहीं थी। विचाराधीन पुरस्कार में निम्नलिखित निष्कर्ष स्पष्ट हैं: -

" 52. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस पर निर्भरता रखी गई है

बी. एच. ई. एल.-जी. ई. गैस टर्बाइन नामक ओ. ई. एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र

सर्विसेज, प्राइवेट लिमिटेड दिनांक 8 नवंबर, 2005। ओ. ई. एम. द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि दावेदार के गोवा संयंत्र के चालू होने के बाद गैस टर्बाइन का अनुशंसित निरीक्षण किया गया और टर्बाइन को बिना किसी क्षरण के रेटेड आउटपुट का उत्पादन करते हुए पाया गया। इसी तरह, बीजीजीटीएस ने वार्षिक अवधि के दौरान जीटी का गर्म गैस पथ निरीक्षण किया था।

सितंबर 2005 में निरीक्षण। सभी संचालन मापदंड थे

पौधे का कोई क्षरण नहीं होना। डिग्रेडेशन और डाउन रेटिंग दो अलग-अलग और अलग अवधारणाएं हैं जिन्हें भ्रमित नहीं किया जा सकता है। एक-दूसरे के साथ। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि डाउन रेटिंग केवल तभी आवश्यक हो जाती है जब इसमें गिरावट हो।

पौधा।

54. दावेदार ने 5 अप्रैल 2007 को पक्षों के बीच हुई बैठकों का भी उल्लेख किया है, जब प्रतिवादी ओ. ई. एम. की सिफारिश के अनुसार अनुबंधित क्षमता की डाउन रेटिंग से संबंधित मुद्दे पर विधिवत संतुष्ट था, जिस पर उक्त समिति में चर्चा की गई थी। दावेदार ने समझाया कि संयंत्र का रखरखाव ओ. ई. एम. की सिफारिश के अनुसार किया गया था और अनुबंधित क्षमता की कोई डाउन रेटिंग नहीं थी। दावेदार ने इस संबंध में पहले ही ओ. ई. एम. का पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जो 8 नवंबर 2005 का है। उक्त बैठक में पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि उक्त बैठक में जो कहा गया था, उसके अनुसार चालानों का मिलान किया जाना चाहिए और भविष्य के सभी चालानों की गणना उसी तरीके से की जानी चाहिए।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कार्यवृत्त। वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5 अप्रैल 2007 की उक्त बैठक को रिकॉर्ड में रखा गया है। इस प्रकार, अनुबंधित क्षमता की डाउन रेटिंग का सवाल पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यह विवादित नहीं है कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त और उस पर हुए समझौते के आधार पर अप्रैल 2004 से अप्रैल 2007 की अवधि के लिए चालान का मिलान किया गया और प्रत्यर्थी द्वारा पुनर्विचार को विधिवत मंजूरी दी गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा दावेदार को उसके आधार पर भुगतान किया गया था। भविष्य के सभी चालान बैठक में हुए उक्त समझौते के आधार पर उठाए गए थे और चालान विधिवत किए गए थे।

उत्तरदाता द्वारा अनुमोदित और उत्तरदाता द्वारा भुगतान किया गया है

मार्च 2013 तक की अवधि और अप्रैल 2013 के एक हिस्से के लिए। इन परिस्थितियों में, इसलिए, संयंत्र की क्षमता की डाउन रेटिंग से संबंधित मुद्दे को बीच में सुलझा लिया गया प्रतीत होता है पक्षकारों को, और इस कार्यवाही में फिर से उत्तेजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस दावे को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

08.11.2005 और इस बारे में कि क्या दावेदार उस आधार पर कोई दावा कर सकता था या नहीं। उच्च न्यायालय बैठक के कार्यवृत्त का विश्लेषण करने के लिए भी आगे बढ़ा। यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक विशेष साक्ष्य के साथ मूल्य और मूल्य का मामला है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संतोषजनक नहीं माना गया था; और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा सरकार के तर्क को अस्वीकार करना गलत पाया गया था। हालाँकि, इसके बाद, उच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि यह यह साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का मामला नहीं था, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण, पेटेंट अवैध था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

" 124. विवादित पुरस्कार ने 8 नवंबर 2005 के प्रमाण पत्र में गंजे बयान के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है और संयंत्र का कोई क्षरण नहीं हुआ था और आगे, संयंत्र के क्षरण के अभाव में, डाउनरेटिंग की अवधारणा लागू नहीं होगी, फिर से, यह सम्मान के साथ, पेटेंट अवैधता है। इस प्रमाणपत्र को शायद ही ओ. ई. एम. की सिफारिश माना जा सकता था। किसी भी मामले में, प्रमाण पत्र में क्षरण की अनुपस्थिति [2023] 8 एस. सी. आर. का उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2005 में, और इस तरह के प्रमाण पत्र के आधार पर, यह अनुमान लगाने का कोई सवाल ही नहीं था कि उसके बाद भी संयंत्र का कोई क्षरण नहीं हुआ था। इसलिए, संविदात्मक शर्त डाउनरेटिंग से संबंधित है, जिसे किसी भी द्वारा कभी संशोधित या हटाया नहीं गया था। 8 नवंबर 2005 के प्रमाण पत्र या कार्यवृत्त के आधार पर बाद के समझौतों को नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता था

5 अप्रैल 2007 की बैठक।

125. विवादित पुरस्कार इस हद तक कि यह अपीलार्थी के निर्णय को अस्वीकार कर देता है।

इसलिए, अवमूल्यन के आधार पर विवाद को इस आधार पर अलग करना होगा कि यह अभिलेख के सामने पेटेंट अवैधता से दूषित है। आक्षेप में दर्ज किए गए निष्कर्ष

पुरस्कार केवल 8 नवंबर 2005 के प्रमाण पत्र और 5 अप्रैल 2007 की बैठक के कार्यवृत्त पर आधारित हैं। किसी भी दस्तावेज़ से यह नहीं पता चलता है कि डाउनरेटिंग की संविदात्मक अवधि को या तो समाप्त कर दिया गया था या उसका पालन किया गया था। यह न तो अभिलेख पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का मामला है और न ही साक्ष्य की कमी। यह बिना किसी सबूत का मामला है। यह एक

गलत तरीके से यह मानकर संविदात्मक प्रावधान की अनदेखी करने का मामला कि इस तरह के प्रावधान को संशोधित या हटा दिया गया था। इसके विपरीत, संभावित निष्कर्ष, इसलिए, प्रत्यक्ष रूप से विकृत हैं और अभिलेख के सामने पेटेंट अवैधता से पीड़ित हैं। विवादित पुरस्कार, इस हद तक कि यह अवमूल्यन के मुद्दे पर अपीलार्थी के बचाव को खारिज कर देता है और रुपये का पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ता है। 18.53 प्रत्यर्थी के पक्ष में करोड़ रुपये जमीन पर अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है।

विकृति और पेटेंट अवैधता "।

अधिनियम की धारा 34 के तहत विचार की सीमा के भीतर, उस क्षेत्र में प्रवेश किया है जो विशेष रूप से मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है। इस मद के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया है, वह विशेष रूप से अभिलेख पर साक्ष्य और प्रासंगिक आसपास के तथ्यों/कारकों पर उसका विचार था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत या पेटेंट अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है ताकि इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही दो विचार संभव हों, न्यायालय अपने स्वयं के दृष्टिकोण को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

25. अवमूल्यन से संबंधित मुद्दे के संबंध में विद्वान महान्यायवादी द्वारा उठाए गए प्रश्न, कि ओ. ई. एम. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का उत्पादन करने में विफलता के लिए दावेदार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पुरस्कार के खिलाफ अपील/संशोधन और इस तरह, उन सिद्धांतों का फिर से उल्लंघन करना कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में साक्ष्य की पुनः प्रशंसा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह प्रति बल दोहराया जाता है कि एक पुरस्कार को "पेटेंट" से पीड़ित कहा जा सकता है। अवैधता "केवल तभी जब यह पुरस्कार के सामने स्पष्ट रूप से एक अवैधता है और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए। प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में प्रस्तुतियाँ स्वयं हैं

1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के लोकाचार के प्रतिकूल हैं और इन्हें अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

25.1 . दूसरे शब्दों में, जहां तक डाउनरेट करने के प्रश्न का संबंध है, दिनांकित 08.11.2005 प्रमाण पत्र के मूल्य से संबंधित प्रश्न और दावेदार द्वारा इस मुद्दे को पहले नहीं उठाने का प्रभाव फिर से सीधे साक्ष्य की सराहना के क्षेत्र में आएगा और संभावनाओं की प्रधानता पर निष्कर्ष को प्रस्तुत करने की सीमा तक पहुंच जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष साक्ष्य के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण लिया है। यदि यह पुरस्कार के खिलाफ अपील होती, तो न्यायालय का दृष्टिकोण अलग हो सकता था, लेकिन अधिनियम की धारा 34 की सीमा के भीतर पुरस्कार की जांच करते समय ऐसा नहीं था। हम इस संबंध में भी यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि निचली अदालत की डिग्री के खिलाफ नियमित अपील में भी, अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित निर्णय में त्रुटि के बारे में विशेष रूप से निष्कर्ष दर्ज किए बिना अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

चुनौती। किसी भी मामले में, यदि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, तो परिणाम केवल प्रत्येक पुरस्कार को उन आधारों पर न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील बनाने का होगा जो

अन्यथा, अपील या पुनरीक्षण के हैं और जिन्हें विधानमंडल द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत लेने की अनुमति नहीं है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. यह पता लगाने के बाद कि उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए दो प्रमुख मुद्दे 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर नहीं हैं, हम फिर से देख सकते हैं कि 4 मेगावाट बिजली और जाली के सिद्धांतों पर परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित अन्य दो तुलनात्मक रूप से छोटे मुद्दों के संबंध में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण भी उसी त्रुटि से ग्रस्त है, जहां उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण किया है ताकि यह माना जा सके कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने प्रस्तावों या निष्कर्षों में सही नहीं रहा है।

4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क से संबंधित पुरस्कार

27. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की, अर्थात् 02.01.2009 दिनांकित पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्र और

19.01.2009 और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य का यह कहना उचित नहीं था कि संयंत्र की उपलब्ध क्षमता कम हो गई है।

28. इस मद में भी, उच्च न्यायालय ने 02.01.2009 और 19.01.2009 दिनांकित उक्त संचार की पुनः व्याख्या की है जिसके द्वारा पक्षकार सहमत हुए हैं।

गोवा सरकार के लिए आरक्षित बिजली स्टेशन की 19.8 मेगावाट क्षमता में से 15.8 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिलिंग का तरीका शेष 4 मेगावाट को तीसरे पक्ष को बेचने की अनुमति देना और उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य पर तथ्य के एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा। हम 4 मेगावाट बिजली पर परिवर्तनीय शुल्क के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के सारांश को उपयोगी रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं:

" 137. यह परिस्थिति कि निश्चित लागतों के भुगतान को छोड़कर एक विशिष्ट खंड था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि

अपीलार्थी ने इस 4 मेगावाट बिजली के संबंध में परिवर्तनीय लागतों को वहन करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो परिवर्तनीय लागतें अपीलार्थी द्वारा मूल पी. पी. ए. या पी. एस. ए. और पूरक पी. पी. ए. के संदर्भ में प्रत्यर्थी को अन्यथा देय नहीं थीं। अगर कोई था

अपीलार्थी को अनुबंध के तहत उसके द्वारा लगाए गए शुल्कों के अलावा किसी भी शुल्क के साथ बोझिल करने का प्रस्ताव, तो निश्चित रूप से यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था। इस तरह के अतिरिक्त बोझ को निहितार्थ द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, यह तर्क कि क्योंकि इसमें परिवर्तनीय आवेशों का कोई संदर्भ नहीं था

दिनांक 19.1.2009 का संचार, उसी का भुगतान करने के लिए सहमत था अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य काफी विकृत है और अभिलेख के सामने पेटेंट अवैधता का गठन करता है। हमारे अनुसार, विवादित पुरस्कार इस हद तक कि यह प्रतिवादी को रुपये की सीमा तक अन्यायपूर्ण रूप से

समृद्ध करता है। 3.94 नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ करोड़ों का टकराव। विवादित पुरस्कार, इस हद तक, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा भी दूषित किया जाता है।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अनुचितता, विकृति, और पेटेंट अवैधता पर स्पष्ट रिकॉर्ड का चेहरा "।

29. उच्च न्यायालय ने एक बार फिर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित क्षेत्र में कदम रखा है। यह देखा गया है कि पार्टियों ने

15. 8 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिलिंग की एक विशेष पद्धति पर सहमति व्यक्त की, लेकिन साथ ही, भविष्य में किसी भी समय 19.8 मेगावाट आपूर्ति पर वापस जाने का अधिकार उनके पास बरकरार रखा। पक्षों के लेन-देन के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मामले पर एक विशेष दृष्टिकोण रखा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्वीकार्य या अविश्वसनीय था। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी।

नेट आउट सिद्धांत से संबंधित पुरस्कार

30. नेट आउट का पहलू, फिर से, पक्षों के अनुबंध की शर्तों और साक्ष्य से प्राप्त की जाने वाली कटौती पर निर्भर करता है।

रिकॉर्ड में। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 13.09.2014 और 18.09.2014 दिनांकित टिप्पणियों के आधार पर विशेष निष्कर्ष निकाला था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ गोवा सरकार द्वारा दावेदार को बिजली की आपूर्ति से संबंधित अनुबंध के प्रावधानों पर विचार किया, जब मई 2014 से अगस्त 2014 की अवधि के लिए बिजली केंद्र बंद था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आगे संचार का उल्लेख किया जिसमें गोवा सरकार का निर्णय भी शामिल है कि बंद अवधि के दौरान दावेदार को किस दर पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि एक निश्चित दर जिसे पीपीए के प्रावधानों के अनुसार गुणा नहीं किया जाना था, दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई थी। पुरस्कार ने इस तरह की खोज के कारण भी बताया। भले ही यह माना जाए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ऐसा दृष्टिकोण लिया है जो उचित नहीं है।

विचारशील और विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी ले सकता था।

31. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस मद में अपने हस्तक्षेप को फिर से उचित ठहराया है: -

" 148. हमारे अनुसार, नेट आउट के पहलू पर विवादित पुरस्कार फिर से विकृति और पेटेंट अवैधता से दूषित हो जाता है। आई. डी. 1 दिनांकित नोट के साथ-साथ 18/9/2014 दिनांकित संचार अपने सादे शब्दों में केवल रुपये की दर के निर्धारण को संदर्भित करता है। 3.78 पी. के. डब्ल्यूएच. अनुबंध संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए

जाल के बारे में। यह नोट या यह संचार आवश्यक था क्योंकि प्रासंगिक निकटवर्ती बिलिंग अवधि के लिए [2023] 8 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कोई आपूर्ति नहीं की गई थी और इसलिए कोई तैयार दर उपलब्ध नहीं थी जिसके आधार पर संविदात्मक प्रावधानों पर काम किया जा सके। इसलिए, अपीलार्थी ने रुपये की दर निर्धारित की। 3.78 पी. के. डब्ल्यूएच. नेट आउट के उद्देश्यों के लिए आधार दर के रूप में। नोटिंग में या दिनांकित 18/9/2014 संचार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से यह सुझाव दे कि इस तरह की आधार दर का निर्धारण करके, पक्षों का इरादा था

इस आधार दर को 1.25 में गुणा करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट संविदात्मक प्रावधानों को पूरी तरह से मंजूरी देना ताकि एक अनिर्धारित बंद की स्थिति में लाभ उठाया जा सके।

प्रत्यर्थी द्वारा बिजली संयंत्र को बंद करना। इसलिए, नोटिंग और दिनांक 18/9/2014 के संचार के आधार पर, निष्कर्ष या निष्कर्ष कि पक्षकारों ने इसे समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी

स्पष्ट और विशिष्ट संविदात्मक प्रावधान, एक प्रशंसनीय निष्कर्ष या निष्कर्ष भी नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष या निष्कर्ष को अभिलेख के सामने विकृति और पेटेंट अवैधता से दूषित किया जाता है। द. रुपये की राशि का पुरस्कार। 2.36 इसलिए, इस आधार पर प्रत्यर्थी को दिए गए करोड़ रुपये (लगभग), विकृति और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है।

रिकॉर्ड करें "।

31.1 . इस विषय पर भी, उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित किया है और पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए अपने समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः व्याख्या की है। अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय के लिए इस तरह के दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी अनुमति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

पुरस्कार में रुचि

32. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को ब्याज के संबंध में अपने तर्क को खारिज नहीं करना चाहिए था

पूर्व-संदर्भ अवधि क्योंकि ब्याज का भुगतान करने की देयता केवल तभी उत्पन्न होगी जब भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित हो जाएगी।

32.1 . ब्याज के प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण निम्नलिखित में उचित था -

संविदात्मक प्रावधान और अधिनियम की धारा 31 (7) के प्रावधान; और पूर्व संदर्भ अवधि और उस अवधि के लिए ब्याज के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया है जिसके दौरान कार्यवाही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी। हमारे विचार में, राज्य का यह तर्क देना सही नहीं है कि ब्याज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दौरान नहीं दिया जा सकता था।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

मध्यस्थ के संदर्भ की अवधि। इस पहलू के संबंध में, इस प्रभाव के लिए प्रस्तुतियाँ कि पूर्व-संदर्भ अवधि का ब्याज किसी भी बाध्यकारी कारणों पर आधारित नहीं था और ब्याज के लिए संविदात्मक प्रावधान क्षेत्र में थे, खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, केवल 1996 के अधिनियम की धारा 34 की परिधि के भीतर भी नहीं होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

33. तथापि, जहां तक अधिनिर्णय के बाद की अवधि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीकों से ब्याज की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है:

वेदांत लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांतों पर भरोसा किया है और ब्याज की दर को घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है।

" 175. श्री भट ने भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दरों (बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स) का संकेत देते हुए एक बयान सौंपा। 2017-18 अवधि के लिए, इंगित दरें लगभग 13 से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मौजूदा आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है।

शर्तें जब विवादित पुरस्कार दिया गया था। पुनः, दी गई मूल राशि पर ब्याज के रूप में दी गई राशि की आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए भी संदर्भ आवश्यक है। ऊपर उल्लिखित सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का अधिनिर्णय अत्यधिक और आनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांत के विपरीत है और इसे घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करना होगा। वेदांता लिमिटेड (ऊपर) में, पुरस्कार दिनांकित था 9/11/2017 और न्यायालय ने INR के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया।

घटक। विवादित पुरस्कार, हमारे मामले में, 16/को दिया गया था।

2/2018 . "

34. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज दर में उपरोक्त कमी भी अनुचित है। हमने देखा है कि

धारा 31 (7) (बी) के प्रावधानों में कहा गया है कि जब तक पुरस्कार अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक मध्यस्थ पुरस्कार के तहत देय राशि पर पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण में "ब्याज की वर्तमान दर" अभिव्यक्ति का वही अर्थ समझाया गया है जो ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2 (बी) के तहत दिया गया है। उच्च न्यायालय ने वेदांता लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक न्यायालय मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज को कम कर सकता है जब ऐसा ब्याज [2023] 8 एस. सी. आर. को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रचलित आर्थिक स्थिति या जहाँ यह उचित नहीं पाया जाता है या जहाँ यह न्याय के हित को बढ़ावा देता है। हम ब्याज की दर को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई आधार नहीं पाते हैं, जैसा कि वेदांता लिमिटेड के मामले में था, जिसमें यह न्यायालय रुपये के साथ-साथ यूरो घटकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर विचार कर रहा था। इसके अलावा, वेदांता लिमिटेड के मामले में, विदेशी मुद्रा घटक के संबंध में ब्याज की दर को कम कर दिया गया था ताकि

अंतर्राष्ट्रीय दर के अनुरूप ब्याज दर इस आधार पर कि भारत में रुपये के ऋण और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर प्रचलित ब्याज दर अलग-अलग थी और अंतर्राष्ट्रीय दरें कम थीं। वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है। 34.1 . ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया है। इसके विपरीत, जैसा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है

उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर होने के कारण प्रचलित ब्याज दर 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा में थी।

15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए अधिनियम की धारा 31 के तहत इसके अधिकार क्षेत्र में और इसे घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं था। हम इस संबंध में अवलोकन कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय किसी भी इक्विटी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा था ताकि ब्याज की दर को फिर से निर्धारित किया जा सके - इसके द्वारा उपयुक्त माना जाता है। यह एक वाणिज्यिक विवाद में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित मामला था।

अंतिम टिप्पणियां, अवलोकन और निष्कर्ष

35. पूर्वगामी चर्चा में, हमने अपने दिनांकित आदेश में वाणिज्यिक न्यायालय की चर्चाओं और निष्कर्षों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है

12.09.2019 . इसके बजाय, हमने सीधे उच्च न्यायालय के विचार के साथ-साथ विचाराधीन पुरस्कार पर विचार किया है। जैसा कि देखा गया है, यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार के गुण-दोष से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है। हालाँकि, निष्कर्ष निकालने से पहले, हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि वाणिज्यिक न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में मामले से निपटने के दौरान निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले भौतिक मुद्दों की जांच नहीं की थी।

35.1 . यह देखा गया है कि पक्षों की दलीलों पर ध्यान देने के बाद, वाणिज्यिक न्यायालय ने इसके लिए सटीक रूप से बिंदु तैयार किए:

निर्धारण और फिर, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के प्रत्येक बिंदु पर विचार किया गया। इस संबंध में, हम उच्च न्यायालय को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को उचित नहीं पाते हैं।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

द्वारा निर्धारण के लिए बिंदुओं को तैयार करने के बारे में टिप्पणी करने में

वाणिज्यिक न्यायालय और फिर यह देखते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय ने केवल पुरस्कार के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत किया। धारा 34 आवेदन पर विचार करने वाला वाणिज्यिक न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। फिर भी, लंबे समय से चली आ रही दलीलों को देखते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय ने उठाए गए मुद्दों को गिना और फिर अभिलेख की जांच करने के बाद निष्कर्षों को वापस कर दिया

और राज्य की ओर से की गई प्रस्तुतियों को अस्वीकार करते हुए। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी, जिसमें 1996 के अधिनियम की धाराओं की परिधि के भीतर और मापदंडों पर उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया था। हम, उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 49 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां परिवर्तनीय शुल्क के मुद्दे के संबंध में, पक्षों के सभी तथ्यात्मक पहलुओं और दलीलों पर ध्यान देने के बाद, वाणिज्यिक न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" 49. उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जी. ओ. जी. ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया

और यह समझ लिया कि बिजली की कीमत की गणना ईंधन की कीमत और डॉलर रूपांतरण दर के आधार पर की जानी थी और 30.08.2013 दिनांकित पत्र और कैबिनेट नोट पक्षों के बीच समझ को जानने के लिए एक मार्गदर्शक कारक थे। एल. डी. मध्यस्थ ने उचित रूप से सराहना की कि जी. ओ. जी. के मंत्रिमंडल ने स्पष्ट रूप से दावेदार के पक्ष में निर्णय लिया। एल. डी. महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मंत्रिमंडल का निर्णय बाध्यकारी नहीं था क्योंकि इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और न ही दावेदार को कोई निर्णय बताया गया था। बचित्तर सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक मंत्रिमंडल के निर्णय का राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए औपचारिक आदेश द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तब तक इसका बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। एल. डी. महाधिवक्ता ने भी निर्णय का संदर्भ दिया बॉम्बे केमिकल्स लिमिटेड का मामला बनाम। भारत संघ-2006 (201) ई. एल. टी. 167 बॉम्बे जिसमें कैबिनेट नोट पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया था, लेकिन यह माना गया था कि कैबिनेट नोट केवल बजटीय प्रावधान करने के लिए था। पूर्वाग्रह के बिना एल. डी. महाधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि भले ही कैबिनेट नोट पर विचार किया जाए, यह अधिक से अधिक रुपये की राशि के लिए हो सकता है। 0.76 पैसा बढ़ता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वर्तमान मामले में परिवर्तनीय ईंधन मूल्य के आधार पर भुगतान करने में जी. ओ. जी. के बाद के आचरण से पता चलता है कि उन्होंने उक्त कैबिनेट निर्णय को लागू किया। वर्तमान मामले में भले ही उक्त कैबिनेट नोट को आंतरिक नोट माना जाए, लेकिन इस पर विचार करना होगा क्योंकि जी. ओ. जी. ने परिवर्तनीय ईंधन मूल्य और [2023] 8 एस. सी. आर. को स्वीकार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुगतान भी किया। इसके बाद भुगतान करना परिवर्तनशील होता है।

कारक जो उपरोक्त दो निर्णयों को अलग करते हैं।

ऊपर वर्णित कारणों के लिए, बिंदु संख्या 1 का उत्तर दिया गया है।

सकारात्मक में "।

36. "पेटेंट अवैधता" के संकीर्ण दायरे का उल्लंघन केवल विभिन्न अभिव्यक्तियों के उपयोग से नहीं किया जा सकता है जो फिर भी केवल

" त्रुटि "और" पेटेंट अवैधता "के लिए नहीं। हम दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है और रेखांकित किया गया है उसे दोहराने के लिए प्रेरित हैं कि न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की वैधता की जांच करते समय संयम दिखाने की आवश्यकता है, अन्यथा तथ्यात्मक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद पुरस्कार में हस्तक्षेप 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। यह इस तथ्य के अलावा है कि इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई न्यायिक निर्णयों को निरर्थक बना देगा यदि मध्यस्थता पुरस्कारों को इन अभिव्यक्तियों की रूपरेखा की सराहना किए बिना उन्हें "विकृत" या "स्पष्ट रूप से अवैध" के रूप में वर्गीकृत करके अलग कर दिया जाता है।

37. पारित करते समय, हम यह ध्यान में रखने में मदद नहीं कर सकते कि विवादित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने हालांकि द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया है इस न्यायालय ने सांगयोग इंजीनियरिंग (ऊपर) में, लेकिन फिर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक विश्लेषण को पुनः प्रस्तुत किया और इस प्रकार निकाले गए अंशों के संदर्भ में मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। के साथ

वे उपलब्ध थे और उन सिद्धांतों के संदर्भ में मामले से निपटने की आवश्यकता थी। इस पहलू को उस पर छोड़ते हुए, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह निरीक्षण करना पर्याप्त होगा कि विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश, जहां तक यह प्रश्नगत पुरस्कार के निष्कर्षों और निष्कर्षों में हस्तक्षेप करता है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखने की आवश्यकता है।

38. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए सम्मानित राशि और सहायक पहलुओं की गणना के संबंध में विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई कुछ अन्य दलीलों के लिए रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आवश्यकता नहीं है।

वी. गोवा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विस्तृत चर्चा। तथ्य यह है कि पेटेंट का कुछ भी नहीं है

पुरस्कार के चेहरे पर स्पष्ट अवैधता की ओर इशारा किया गया है। प्रस्तुतियाँ अनिवार्य रूप से मामले के गुण-दोष पर कुछ कथित त्रुटियों का संकेत देती हैं जो, जैसा कि देखा गया है, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के मापदंडों के भीतर नहीं आती हैं।

39. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.03.2021 के विवादित निर्णय और आदेश के उस हिस्से को, जो दिनांकित 16.02.2018 के पुरस्कार और दिनांकित 12.09.2019 के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को संशोधित करता है, अलग कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, विचाराधीन पुरस्कार को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाता है।

40. दावेदार द्वारा दायर अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है और राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपीलों

का निपटारा किया गया।

निधि जैन (सहायक: शेवाली मोंगा और शाश्वत जैन, एलसीआरए)